● वर्ष-2
● अंक-208
रायपुर, शनिवार
22 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पुंछ में आतंकी हमले पर आक्रोश

प्रदेश में जगह-जगह पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले फूंके

जम्मू कश्मीर । जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हुए आतंकी हमले ने देश के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया है। जगह-जगह लोग इस हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर यह मामला अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। इस बीच, एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां तक विरोध प्रदर्शनों की बात है तो उसका असर जम्मू में सर्वाधिक देखने को मिला जहां कई संगठनों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के नेता युद्धवीर सेठी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कच्ची छावनी इलाके में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाये और तख्तियां लहराईं। सेठी ने संवाददाताओं से कहा, ''हम अपने जवानों की मौत का बदला लेंगे। हम कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को और मजबूत करेंगे।'' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास को अवरुद्ध करने के लिए हमला किया गया, लेकिन प्रशासन झुकेगा नहीं। इस घटना के खिलाफ एक अन्य प्रदर्शन स्थानीय संगठन मिशन स्टेटहुड जम्मू-कश्मीर ने भी किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पाकिस्तानी झंडे और पुतले जलाये। संगठन के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने आरोप लगाया कि पुंछ हमला केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन की पूरी तरह नाकामी का परिणाम है। वहीं, शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बृहस्पतिवार को एक आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से पांच जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को हुए हमले में शहीद हुए पांच जवानों में

से चार पंजाब के हैं। सीएम भगवंत मान ने सभी जवानों की शहादत पर शोक जताया है। शहीद हुए जवानों में मनदीप सिंह निवासी गांव-चकोइयां कलां लुधियाना, हरिकृशन सिंह निवासी तलवंडी भारथ गुरदासपुर, कुलवंत सिंह निवासी चडिक मोगा और सेवक सिंह बाघा बठिंडा शामिल हैं।

सेना ने यह जानकारी दी। सेना ने एक बयान में कहा है कि हमले में शहीद होने वाले सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और इलाके में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए थे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस घटना के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, ''जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में हुई त्रासदी से दुखी हूं, जहां एक वाहन में आग लगने के बाद भारतीय सेना ने अपने बहादुर जवानों को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।''

सुरक्षा में चूक हुई है-फारूक अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बृहस्पतिवार को हुए एक आतंकवादी हमले में पांच जवानों के शहीद हो गए। फिलहाल आतंकियों की तलाश के लिए बाटा-डोरिया क्षेत्र के एक घने जंगल में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाश अभियान शुरू किया है। इस सब के बीच पुंछ में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कांफ्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीमा के करीब है। कहीं न कहीं तो सुरक्षा का मामला होगा, इनको सुरक्षा की जांच करनी चाहिए थी। 5 जवानों की मृत्यु हो गई, गलती तो कहीं हुई है और इनको देखना चाहिए। इस घटना पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि पुंछ में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मारे गए सेना के जवानों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।

शहीदों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान ने कहा कि पुंछ आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सेना के चार जवानों के परिवारों को हम एक-एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देंगे। इससे पहले आतंकी हमले में शहीद हुए लांस नायक कुलवंत सिंह के गांव के सरपंच गुरचरण सिंह ने कहा था कि कुलवंत सिंह घर का इकलौता बेटा था, उसके पिता भी कारगिल में शहीद हुए थे। तीन साल पहले इनकी शादी हुई थी। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये गरीब परिवार है इनकी मदद की जाए।

पुंछ में एक आतंकी हमले की भयानक खबर, जिसने ड्यूटी के दौरान सेना के 5 जवानों की जान ले ली। मैं इस जघन्य हमले की निंदा करता हूं और मारे गए लोगों के प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिले।

-उमर अब्दुल्ला, नेकां उपाध्यक्ष

कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से उन्हें गहरा दुख हुआ है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। हम इस कठिन समय में अपने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं।

-अल्ताफ बुखारी, अध्यक्ष- अपनी पार्टी

सेना के वाहन पर हमले और पांच लोगों की मौत की भयानक और दुखद खबर। कायरों द्वारा आतंक के इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा और आतंक का संकट दुखद रूप से कायम है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।

- सज्जाद लोन, अध्यक्ष-पीपुल्स कांफ्रेंस

आतंकवादियों व उनके समर्थकों का जिस प्रकार से कश्मीर में सफाया किया जा रहा है। वैसे ही राजोरी व पुंछ में भी किया जाएगा।

रवींद्र रैना ,भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

इन दिनों

✍ हिमांशु मिश्रा

राहुल गांधी सजा के खिलाफ याचिका नहीं

'मोदी सरनेम' वाले बयान से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो गुरुवार को खारिज हो गई। कहा जा रहा था कि इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, लेकिन अब तक याचिका दायर नहीं की गई है। अब अगले दो दिन कोर्ट बंद रहेगा। इसी बीच, निचली अदालत की तरफ से दिया गया एक महीने का मोहलत भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी जेल जाएंगे? 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने के साथ ही 30 दिन की जमानत दी गई थी। इन्हीं 30 दिनों के अंदर राहुल को ऊपरी अदालत में अपील करना था। ये समय सीमा आज से दो दिन बाद यानी 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। हालांकि, इसके पहले तीन अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ तीन अपील दायर की गई थी। मुख्य याचिका में ष्ट्छरूकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर तीन मई को सुनवाई होगी। दूसरी याचिका में दो साल की सजा पर रोक की मांग की गई। तीन अप्रैल को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। तीसरी याचिका में दोषी ठहराए जाने पर रोक यानी कन्विक्शन पर स्टे की मांग की गई थी। गुरुवार 20 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। मतलब अभी तीन मई तक राहुल पर कोई खतरा नहीं है। इस बीच, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता चली गई। देशभर में कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों को एकजुट किया, लेकिन उस दौरान राहुल ने कोर्ट के फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती नहीं दी। 11वें दिन वह सेशंस कोर्ट पहुंचे। तब उन्होंने तीन याचिकाएं दायर की। उसी दौरान उन्हें अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका को 20 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज इसके खिलाफ राहुल हाईकोर्ट जाने वाले थे, लेकिन अब तक याचिका नहीं दायर हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पार्टी में देश के बड़े-बड़े अधिवक्ता हैं, वो अपने नेता के बचाव में तुरंत क्यों नहीं ऊपरी अदालतों का रुख कर रही है? ये तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस मामले में धीमी गति से फैसले ले रही है। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस खुद इस मामले को लंबा चलाना चाहती हो ताकि इसका फायदा उसे चुनावों में मिल सके। वह लोगों को यह बताना चाहती है कि चूंकि राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह का षडयंत्र चल रहा है। कांग्रेस को इसका फायदा हो या न हो, लेकिन विपक्ष जरूर इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसी का हवाला देकर कांग्रेस 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हो।

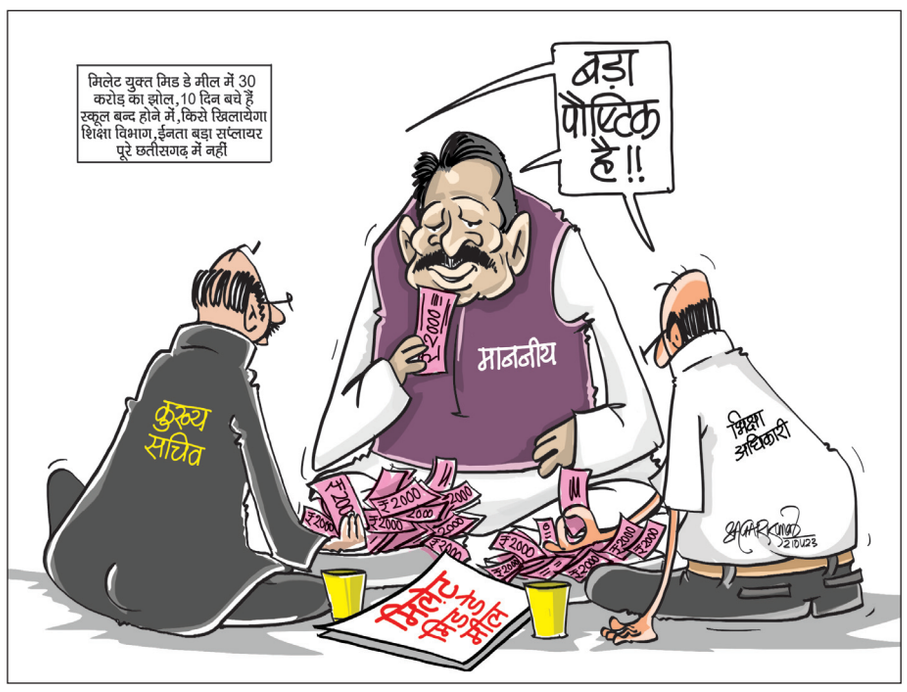

आरक्षण विधेयक को लौटाने की खबर का राजभवन ने किया खंडन

■ गैर जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दें- केदार कश्यप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर विवाद खमता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधेयक पर राजभवन की स्वीकृती नहीं मिलने को लेकर बयान दे रहे है। इस बीच शुक्रवार की सुबह समाचार माध्यमों में यह खबर आई कि राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक को पुर्नविचार के लिए सरकार को लौटा दिया है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री रवीन्द्र चौबे की टिप्पणी भी आई जिसमें उन्होंने आगे की कार्रवाई करने विचार विमर्श करने की बात कही, इसके कुछ देर बाद राजभवन से यह स्पष्टीकरण आया कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जारी किया गया समाचार तथ्यहीन है। इसके बाद भाजपा रवीन्द्र चौबे पर आक्रमण हो गई।

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि उन्होंने आरक्षण विधेयक जैसे गंभीर विषय की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाए जाने का उल्लेख करते हुए टिप्पणियां की हैं और बिना इसकी पुष्टि किए प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा बाद में यह स्पष्ट हो जाने पर कि राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक वापस नहीं लौटाया है, उनका यह कहना कि मीडिया की खबरों के आधार पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, उन्हें जानकारी नहीं है, यह मंत्री के रूप में उनका बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मीडिया की

खबरों पर चल रही है? क्या संसदीय कार्य मंत्री को इतने संवेदनशील विषय में जानकारी नहीं होना चाहिए? आखिर संसदीय कार्य मंत्री कर क्या रहे हैं? राज्य के संसदीय कार्य मंत्री को अपने विषय से जुड़ी जानकारी न होना साबित कर रहा है कि यह सरकार हवा में तैर रही है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना किसी तथ्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन, भाजपा और केंद्र सरकार के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने की जो परंपरा अपना रखी है, उसी का अनुसरण उनके मंत्री कर रहे हैं। राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक सरकार को वापस नहीं लौटाया और संसदीय कार्य मंत्री ने बिना किसी पड़ताल के बयानबाजी करते हुए मंत्री की मर्यादा भंग कर दी। संसदीय इतिहास में ऐसा अजूबा पहली बार सामने आया है। ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम की पटकथा कांग्रेस के दफ्तर में लिखी गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे राज्यपाल और छत्तीसगढ़ की जनता से अपने भ्रामक कृत्य के लिए क्षमा मांगें तथा संसदीय कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दें।

श्री कश्यप ने कहा संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया के सामने यह कहा कि मीडिया के माध्यम से कल जानकारी लगी कि राज्यपाल ने विधेयक लौटाया है यानी कि 1 दिन बाद भी सच्चाई को पता किए बिना संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनकी टिप्पणी आना एक साजिश की तरफ इशारा करता है आरक्षण पर कांग्रेस इसी प्रकार केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है।

प्रमुख समाचार

अमृतपाल की पत्नी को रोकने पर अकाल तख्त व चन्नी नाराज

चंडीगढ़। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भगोड़े खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर हवाईअड्डे पर रोकने पर अधिकारियों की आलोचना की है। कौर को हवाईअड्डे पर उस समय रोका गया जब वह ब्रिटेन के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी। एक वीडियो बयान में ज्ञानी ने कहा कि किरणदीप कौर को अमृतसर के एक हवाई अड्डे पर रोकना सही नहीं था क्योंकि वह अपने माता-पिता से मिलने जा रही थी। उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अगर वह घर जाना चाहती है तो उसे क्यों रोका गया? अगर उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अकाल तख्त प्रमुख ने इसके अलावा कहा कि वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और अगर सरकार उनसे कुछ पूछना या पूछताछ करना चाहती है, तो उन्हें सम्मानपूर्वक उनके आवास पर जाना चाहिए।

उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में वापसी के दिए संकेत

नई दिल्ली। 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बनी हुई हैं। हाल में ही जदयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की पटना वापसी हो चुकी है। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात हुई है, इसको लेकर अब तक विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकातों को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। अमित शाह से क्या बात हुई, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मुझे आवश्यकता महसूस होगी, तब मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगा। कौन सी बात हम आपको बताएंगे और कौन से नहीं यह मेरे ऊपर ही छोड़ दिजिए।

पुलवामा पर बड़ा दावा करने वाले सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन

नई दिल्ली। मेघालय के पूर्व राज्यपाल

सत्यपाल मलिक इन दिनों अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं। कभी जम्मू कश्मीर आतंकी घटना को लेकर बयान सामने आता है तो कभी किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच मध्यस्थता की बात कह डालते हैं। लेकिन अब सत्यपाल मलिक सीबीआई की तरफ से समन मिलने को लेकर चर्चा में हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी की तरफ से जम्मू कश्मीर में दो प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था।

खारघर की घटना पर आक्रामक हुए शरद पवार

मुंबई। महाराष्ट्र में खारघर त्रासदी को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने राज्य सरकार

पर निशाना साधा है। पवार ने खारघर की घटना पर कहा कि यह 100त्न राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक सिटिंग जज को इस घटना की जांच करनी चाहिए और वास्तविक तथ्य सामने आने चाहिए। बता दें कि मुंबई से सटे रायगढ़ के खारघर इलाके में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सत्यपाल मलिक के पुलवामा को लेकर दिए बयान पर भी शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई बातों का खुलासा किया।

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में 170 प्रतिनिधि हुए शामिल

नई दिल्ली। भारत का राजधानी दिल्ली में पहली बार दो दिनों का वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यह संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। वहीं, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं शांति और अहिंसा पर आधारित थीं जो भारतीय दर्शन की अनुकुल थीं। भगवान बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले करीब 30 देशों के 170 प्रतिनिधि आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों में प्रख्यात बौद्ध भिक्षु, विद्वान, राजदूत और राजनयिक शामिल हैं। भाजपा नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भगवान बुद्ध शांति की बात करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। आस-पास अशांति है। उन्होंने कहा कि उस अशांति को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के साथ दूर कर सकते हैं। कुछ देश कट्टरता में विश्वास करते हैं जो ठीक नहीं है।

राजस्थान में तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी कर रहे सचिन पायलट

संतोष पाठक

राजस्थान की जनता का अब तक यही राजनीतिक अंदाज रहा है कि यहां भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कभी भी कोई तीसरी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई है। यदा-कदा बसपा और कुछ क्षेत्रीय नेताओं द्वारा बनाए गए दलों को कुछ सीटें जरूर मिलती रही हैं लेकिन सरकार और विपक्ष की भूमिका भाजपा और कांग्रेस ही निभाती आई हैं। इसमें से एक दल राजस्थान में सरकार चलाता है तो दूसरा विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहता है।

लेकिन राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अशोक गहलोत सरकार में उपमुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट के तेवरों से ऐसा लग रहा है कि वो राजस्थान में इस बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट प्रदेश में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुल कर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन राजनीतिक संदेशों से ऐसा लग रहा है।

बताया जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को सचिन पायलट की राजनीति और भविष्य की रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपा गया है और अगर यह खबर सच है तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि सचिन पायलट इस बार कांग्रेस और भाजपा से अलग हटकर कुछ नया करने की योजना पर काम रहे हैं।

दरअसल, यह माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देकर सचिन पायलट को राजस्थान भेजने वाले राहुल गांधी ने

भी इस बार उन्हें अकेला छोड़ दिया है। महज कुछ साल पहले वर्ष 2018 में सचिन पायलट को कांग्रेस का उभरता हुआ सितारा बताया जा रहा था। 2018 से 2023 तक आते-आते कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के लिए स्थिति लगातार असहज होती चली गई। कांग्रेस पार्टी के रुख से अब यह साफ-साफ नजर आने लगा है कि सचिन पायलट को इस टर्म में सीएम का पद नहीं मिलने वाला है और भविष्य को लेकर भी फिलहाल उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। सचिन पायलट के अनशन के खिलाफ जिस स्पष्ट तरीके से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत का साथ दिया और जिस तरह से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर कांग्रेस विधायकों से वन-टू-वन फीडबैक ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठकर फिलहाल उन्होंने भाजपा के लिए भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि भाजपा भी चुनाव से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज कर सचिन पायलट को अपने पार्टी में शामिल करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। पायलट को भी बखूबी इसका अंदाजा है इसलिए यह कहा जा रहा है कि वे अब प्रदेश की राजनीति में तीसरा मोर्चा खड़ा कर अपनी ताकत साबित करने का प्रयास कर सकते हैं।

राजस्थान से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल तो पहले ही सचिन पायलट को कांग्रेस से इस्तीफा देकर तुरंत नई पार्टी बनाने की सलाह दे चुके हैं। बेनीवाल पायलट की नई पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है और उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने को भी तैयार हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी भी जोर-शोर से राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिस दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे, उस दिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही उनके समर्थन में सामने आई थी। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी पार्टी भी पायलट के मोर्चे में शामिल हो सकती है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और केजरीवाल के साथ मिलकर अगर तीसरा मोर्चा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के समीकरण को भी बिगाड़ सकते हैं लेकिन अगर मायावती की पार्टी बसपा भी उनके गठबंधन में शामिल हो जाती है तो फिर वे राजस्थान की राजनीति में नया इतिहास बना सकते हैं लेकिन अभी इसमें कई किंतु-परंतु भी लगे हुए हैं कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर अपने नए राजनीतिक दल का गठन करने जैसा बड़ा फैसला करने को तैयार हैं? हनुमान बेनीवाल तो उन्हें नेता मान चुके हैं लेकिन क्या मायावती और केजरीवाल राजस्थान में पायलट को नेता मानने को तैयार हैं ? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही छिपे हुए हैं।

प्रदेश सरकार को उखाड़ कर फेंकना है: कौशिक

विधायक धरम लाल कौशिक ने ली कोरबा एवं कटघोरा विधानसभा स्तरीय बैठक

कोरबा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष व बिल्हा विधानसभा के विधायक धरमलाल कौशिक के मुख्य आतिथ्य में कोरबा एवं कटघोरा विधानसभा स्तरीय की बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह, संगठन के सह प्रभारी गोपाल साहू विधानसभा प्रभारी दिनेश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जोगेश लाम्बा, गोपाल मोदी, अशोक चावलानी, पवन गर्ग मनोज शर्मा, नरेंद्र देवांगन पार्षद नगर निगम कोरबा राजेन्द्र राजपूत जिला मंत्री, चुलेश्वर राठौर, सन्तोष देवांगन जिला महामंत्री टिकेश्वर राठिया जिला महामंत्री, श्यामलाल मरावी, अजय दुबे मंच पर उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम सभी मंचस्थ अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूजा अर्चना की गई उसके बाद मंचस्थ अतिथियों के द्वारा उज्जवला योजना,आवास योजना व शौचालय योजना से लाभान्वित महिलाओं को शाल फल भेंटकर सम्मानित किया गया। ततपश्चात जिलाध्यक्ष डॉ राजीव सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे यशश्वी विधायक के द्वारा निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के द्वारा जो जवाब देही उन्हें दी गई है उन सभी की जानकारी ली जाएगी एव आगामी गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक ने बताया कि जिस प्रकार से आगे

विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमे हम सभी को मिलकर कार्य करना है व केंद्र की जो योजना चल रही है उसे घर-घर जाकर बताना है कि यह जो योजना चल रही है इसे केंद्र की भारतीय जनतापार्टी के द्वारा चलाई जा रही है व प्रदेश की धोखेबाज काँग्रेस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से गंगाजल को हाँथ में लेकर झूठे कसम खाई थी किसी भी कार्य मे खरा नही उतरी है ऐसे धोखेबाज सरकार को उखाड़ कर फेंकना है ततपश्चात सभी सदस्यों को दी गई जवाबदेही को क्रमवार जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर कोरबा विधानसभा की बैठक में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष डॉ आलोक सिंह, जिला मंत्री संदीप सहगल, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह प्रभारी पवन सिन्हा, आईटी सेल संयोजक नवदीप नंदा, सोशल मीडिया संयोजक अजय चंद्रा, कोरबा मंडल अध्यक्ष परविंदर सिंह, बालकों मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर सहित सभी पांचों मण्डल के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे ।

वही कटघोरा की बैठक में हरीश थरवानी मण्डल अध्यक्ष हरदीबाजार, धन्नू दुबे मण्डल अध्यक्ष कटघोरा, सूर्य प्रताप मण्डल अध्यक्ष दीपका, लक्ष्मी कैवर्त मण्डल अध्यक्ष बांकी मोगरा, विनोद यादव मण्डल अध्यक्ष भिलाई बाजार, बुधवारा देवांगन, ज्योति पांडेय, लक्की नंदा आई टी सेल संयोजक,अजय धनोंदिया कोषाध्यक्ष कटघोरा मण्डल, राजेन्द्र टण्डन महामंत्री, संजय शर्मा, बजरंग पटेल उपाध्यक्ष नगर पालिका, बैसाखू यादव, पंकज ध्रुवा, समजीत सिंह, कमला बरेठ, बृजेश यादव, रोहित जायसवाल, सतपाल रजक, हनुमान पांडेय, अनुराग दुहलानी, हरबंश पनेसर सहित सभी पांचों मण्डल के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे कार्यक्रम का सफल संचालन जिला महामंत्री सन्तोष देवांगन के द्वारा किया गया ।

एक-एक तेंदूपत्ता खरीदकर कांग्रेस सरकार वादे को निभाए : नन्द किशोर

दंतेवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने तेंदूपत्ता हितग्राहियों के मांगों को लेकर गीदम मण्डल के बड़े तुमनार व गीदम खरीदी केन्द्र में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में संग्रहण कर्ताओ को संबोधित करते हुए मोर्चा के जिला प्रभारी नंद किशोर राणा ने सरकार पर तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाया। राणा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आदिवासी और वनांचल क्षेत्र के रहवासियों का जीना दूभर कर दिया है। भूपेश बघेल की सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ शोषण की पराकाष्ठा कर रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण कर्ताओं के एक-एक तेंदूपत्ता खरीदने के सरकार के द्वारा किया गया वादा को निभाए।

उन्होने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक भाइयों के साथ भी सरकार यही खेल खेल रही है। संग्रहको को बीमा और बोनस का लाभ राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

पूर्व की भाजपा सरकार में संग्राहक भाई बहनों को दिए जा रहे चरण पादुका की योजना को भी कांग्रेस की सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे किए गए थे। लेकिन सत्ता में आते ही अपने सारे वादे भूल गए। एक ओर जहां प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की भूपेश सरकार शोषण की नए कीर्तिमान रच रही है।

भाजपा द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों में किए जा रहे मांगों में प्रमुख रूप से तेंदूपत्ता खरीदी कम से कम 10 से 15 दिन करना, संग्राहको के लिए बोनस, पूर्व की भाजपा सरकार की तरह चरणपादुका वितरण, संग्राहक परिवार के बच्चो के लिए छात्रवृति, तेंदूपत्ता संग्राहक की मृत्यु पर आश्रित परिवार को बीमा राशि दिया जाए, तेंदूपत्ता फड़ मुंशियों को 12000 रुपए मानदेय, तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी घोषित करने की मांग शामिल है। इन मांगों को लेकर आगामी दिनों में एसटी मोर्चा द्वारा डीएफओ कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान धरना प्रदर्शन में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व जिला प्रभारी नंद किशोर राणा सहित जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी व ,जिला अध्यक्ष मुन्ना मरकाम,अन्ति वेक, मासाराम लेकाम, गुड्डी राम, गुड्डी राम, बालसिंह ताती, पाण्डु राम, पतिराम, अनिल ताती, सोमाराम सहित बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा नेतागण एवं जिले के तेंदूपत्ता संग्राहक इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहे।

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़, कई नक्सली घायल

जगदलपुर। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह सुरक्षाबल के जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के घायल होने का दावा किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से कोंटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलपोच्चा, नुलकातोंग और गोमपाड़ के इलाके में नक्सली कमांडर कोसा और मंगडू की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जिसके बाद डीआरजी की टीम को मौके पर पहुंची। डीआरजी के जवान इस अभियान के दौरान सुबह के वक्त जैसे ही बंडा कन्हईगुड़ा पहुंचे। तभी अचानक पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों को देखते ही उनपर फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग होते देख जवानों ने भी मोर्चा संभाल। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से फरार हो गए।

पुलिस ने इस मुठभेड़ में चार से पांच नक्सलियों के घायल होने का दावा किया है। फिलहाल डीआरजी और सीआरपीएफ एक संयुक्त टीम के द्वारा इलाके में सर्च

अभियान चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबल के सभी जवान सुरक्षित बताए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की विस्तृत जानकारी टीम के वापस लौटने के बाद दी जाएगी।

नक्सलियों ने ट्रक में लगाई आग, बैनर लगाकर आमदई खदान को रद्द करने को कहा

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में नक्सलियों का तांडव जारी है। नक्सलियों ने छोटेडोंगर की आमदई माइंस में लगे ट्रक को निशाना बनाया है। जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर ग्राम कापसी और फरसगांव के बीच नया पुल के पास नक्सलियों ने आमदई खदान में लगे एक ट्रक को आग के हवाले किया है। जिससे ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। नक्सलियों ने नारायणपुर छोटेडोंगर आमदई खदान को रद्द करने और निको कम्पनी से जुड़े लोगों मार भगाने की बात बैनर पर लिखी है। मिली जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने शुक्रवार तगड़े सुबह तीन से चार बजे के बीच आमदई माइंस के ट्रक को पेड़ गिराकर रोका और डीजल टैंक को फोड़कर डीजल पूरी गाड़ी में छिड़काव करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया। अभी नारायणपुर ओरछा मार्ग के सड़कों पर आवाजाही रुकी हुई है। नक्सलियों ने जिस वक्त ट्रक पर आग लगाई उस वक्त ट्रक नारायणपुर से छोटेडोंगर लौह अयस्क के लिए जा रहा था।

भाजपा के हस्तक्षेप से साऊदी में बंधक दुर्ग का व्यक्ति पहुंचा सकुशल घर

दुर्ग। छत्तीसगढ़वासी काम की तलाश में दुर्ग जिला के ग्राम डोमा निवासी गोपाल साहू सहित अन्य तीन व्यक्ति साऊदी पहुंचे थे, पर वहा पहुंच कर पता चला कि जिस काम के लिए उसे दलाल ने पैसे ले कर भेजा है, काम उससे बिलकुल अलग है, और काम बहुत कठिन होने के साथ साथ खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है और लगातर 15 घंटे काम करा कर अमानवीय व्यवहार किया जाता है, और वापस जाने की बात कहने पर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, और घर से ऑनलाइन एक लाख रुपये मंगाने की डिमांड की गयीं पैसा मंगाने पर भी नहीं छोड़ा गया,उन्होंने आप बीती फोन के माध्यम से विडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा और मदद की गुहार लगाई परिजन इस बात की जानकारी युवा मोर्चा के नेता नितेश साहू एवम मीडिया प्रभारी आदित्य ताम्रकार को दी और नितेश साहू के नेतृत्व में जन दर्शन में इस विषय को रखा, फिर भी प्रशासन की कोई उचित पहल नही होने पारिजन निराश हो गए, नितेश ने बंधको व परिजनों की पीड़ा को छत्तीसगढ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया राज्य सभा सांसद सरोज पांडे ने इस विषय पर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर

से मुलाकात कर विषय की गंभीरता और बंधकों की पीड़ा को बताया विदेश मंत्री ने तत्काल सऊदी के दूतावास में बात कर गोपाल साहू एवम उनके साथियों के देश वापसी के लिए वीज़ा जारी करने और दोषी कंपनी पर कार्यवाहीं करने की बात कही विदेश मंत्री के बात करने के तत्काल बाद बंधको को एक्जिट वीजा प्रदान किया गया, एवम् बंधकों से कंपनी का व्यवहार भी सामान्य हो गया जिससे वे सकुशल देश वापस आ पाए श्री अरुण साव ने बताया कि हम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, प्रदेश के नागरिक की पीड़ा हमारी पीड़ा है, भारत के नागरिक को कही भी डरने कि जरूरत नही है क्योंकि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत हाथो में है जिनके नेतृत्व का लोहा को पूरा विश्व मानता है नितेश ने बताया की हमे अपने भारत सरकार पर गर्व है जिन्होंने दुर्ग के छोटे से गांव के परिवार की पीड़ा को समझकर पहल की निश्चीत ही मोदी सरकार आम जनता की सरकार है।

कांग्रेस की चिंता करने की बजाय भाजपा और स्वयं की चिंता करे केदार: चंदन

जगदलपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर नारायणपुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की चिंता करने की बजाय केदार कश्यप को भाजपा और स्वयं की चिंता करनी चाहिए। आज नारायणपुर विधानसभा के विकास को देखके मुद्दा विहीन भाजपा के नेता कांग्रेस विधायकों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को खराब परफार्मेंस बताकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं मे भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आज नारायणपुर विधानसभा सभा मे सर्वांगीण विकास हो रहा है चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र मे हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मर्दापाल, छोटे डोंगर मे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन कॉलेज खोला जा रहा है।

नारायणपुर विधान सभा में नवीन तहसीलों कोहकमेटा, छोटे डोंगर, मर्दापाल व भानपुरी की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को राजस्व प्रकरण, जाति, निवास, आय बनाने अब लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। आज गांव-गांव तक पक्की सड़क का

निर्माण हो रहा है, जिससे आवागमन सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित होगी। प्रदेश और नारायणपुर की जनता 15 साल तक भाजपा से त्रस्त थी। भाजपा ने 15 साल तक प्रदेश मे केवल आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और कमिशन खोरी के अलावा कुछ नहीं किया आज कांग्रेस ने सभी वर्गों के साथ न्याय किया है। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से खुश है। आगामी चुनाव मे भी प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर बनी रहेगी हमे पूर्ण विश्वास है। आज पूर्व मंत्री केदार कश्यप को कांग्रेस और कांग्रेसी विधायकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र की जनता भाजपा को नकार चुकी है, चिंता करना ही है तो भाजपाइयों और स्वयं की करे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राज्य शासन द्वारा पीएम मातृ वंदना योजना 2.0 को संचालित करने की दी गई स्वीकृति

कोरबा। राज्य शासन द्वारा 01 जनवरी 2022 से कौशल्या मातृत्व योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही के द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5000 रूपए की एकमुश्त सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। भारत शासन के अंतर्गत जारी नवीन दिशा निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पहले दो जीवित बच्चों के लिए महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए हितग्राही की दूसरी संतान का बालिका होना अनिवार्य है। यह योजना 01 अप्रैल 2022 से प्रभावशील है। निर्देशानुसार प्रथम संतान पर अब दो किश्तों में 5000 रूपए की सहायता तथा द्वितीय बालिका संतान होने पर राशि 6000 रूपए एक किश्त में सहायता दी जाती है। राज्य शासन द्वारा योजना में दोहराव न हो इस हेतु राज्य के व्यय से संचालित कौशल्या मातृत्व योजना का संचालन बंद करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 संस्करण को परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति दी है।

लूट, चोरी और गुम हुए 200 मोबाइल लौटाए

महासमुंद। महासमुंद पुलिस ने 50 लाख कीमत के 200 मोबाइल बरामद किए। इसके बाद उनके मालिकों को वापस किए गए। लूट, चोरी और खोए हुए मोबाइल महीनों बाद पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को गुम मोबाइल संबंधी जानकारी साइबर सेल को देने के निर्देश दिए थे। साइबर सेल की टीम बीते कई महीनों से गुम मोबाइल की तकनीकी जानकारी जुटाकर जांच कर रही थी। साइबर सेल के स्पेशल साइबर डेस्क ने अथक प्रयास से थाना क्षेत्रों में लूट, चोरी और गुम हुए लगभग 200 मोबाइल फोनों को बरामद किया है। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये है।

3 स्पा सेंटरों में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर कराए गए बंद

अंबिकापुर। अंबिकापुर में संचालित स्पा सेंटरां को लेकर सरगुजा पुलिस को मिली शिकायतों के बाद एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तीन स्पॉ सेंटरों में दबिश दी। स्पा सेंटरों के संचालन का वैध लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने तीनों स्पा सेंटरों को बंद करा दिया है। कार्यस्थल पर महिला लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमा के पालन नहीं किए जाने के कारण संचालकों को नोटिस थमाया गया है। एएसपी विवेक शुक्ला, सीएसपी स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम द्वारा गांधीनगर स्थित एक स्पा सेंटर एवं थाना कोतवाली थानाक्षेत्र में संचालित दो स्पा सेंटरों की औचक जांच की गई। स्पा सेंटरों के संचालक जांच के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने तीनों स्पा सेंटरों को बंद करा दिया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों का पालन नहीं होना पाया जाने पर स्पा सेंटर संचालकों को वैधानिक नोटिस दिया गया है।

आईपीएल पर सट्टा लगवाने वाला आरोपी गिरफ्तार

कांकेर। आईपीएल सीजन के शुरू होते ही सट्टे बाजार भी गर्म होने लगता है। जिसको लेकर ऑफलाइन सट्टा खेला और खिलाया जाता है। कांकेर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे एक सटोरिए को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कांकेर नगर के राजापारा निवासी यश जैन एक लाख 32 हजार रुपए का लेनदेन करने का हिसाब भी पाया गया है। सटोरिए के पास से नगद 13 सौ रुपए भी बरामद किए गए हैं। कांकेर कोतवाली प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि सुभाष वार्ड मछली बाजार के पास यश जैन नाम का एक व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैच में हार जीत का दाव लगाकर ऑनलाइन सट्टा लिख रहा है। आरोपी के कब्जे से 1340 रुपया नकदी रकम एक मोबाईल फोन बरामद हुआ है।

थाना परिसर में लगी आग कई गाड़ियां जलकर खाक

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के

भटगांव थाना परिसर में भीषण आग लग गई। धू-धू करके वहां खड़ी 30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की लपटे इतनी तेज थी कि एक के बाद एक दो पहिया वाहन जलकर आग का गोला बनते चले गए। हालांकि कुछ देर बाद दमकल की गाडियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। दरअसल, भटगांव थाना परिसर के पास एक खेत है। जहां पर पराली में आग लग गई थी। जैसे-जैसे पराली जलती गई वैसे-वैसे थाना परिसर में रखे वाहन जलकर तबाह हो गए। काफी देर तक इस बात की खबर पुलिस प्रशासन को भी नहीं लगी। हालांक दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फ्लिहाल पुलिस आग लगने की वजह क्या है, इस पर जांच कर रही है।

नलों में न लगाए टूल्लू पम्प, ताकि सभी को मिले पेयजल : महापौर

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपील करते हुए कहा है कि घर के नलों व पाईप लाईनों में टूल्लू मोटर पम्प आदि लगाकर पानी न खींचे, इससे पानी प्रेशर कम होता है तथा अन्य लोगों को पर्याप्त रूप से पेयजल प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है, उनके घरों में जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पहुंच पाता है। उन्होने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इसकी जांच करें एवं जिन लोगों द्वारा टूल्लू पम्प लगाएं जा रहे हैं, उनके पम्पों को हटाने की कार्यवाही कराएं।

महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्र. 14 पम्प हाउस मैंगजीनभांठा पहुंचकर निगम के पेयजल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ घर-घर भ्रमण कर पानी की आपूर्ति व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान बस्तीवासियों ने बताया कि कतिपय लोगों द्वारा पाईप लाईन व नल कनेक्शन में टूल्लू मोटर पम्प लगाकर पानी खींचा जा रहा है, जिसके कारण पाईप का प्रेशर नहीं बनता तथा उनके घरों में

पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। महापौर प्रसाद ने इन लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे नल कनेक्शन व पाईप लाईन में टूल्लू पम्प न लगाएं ताकि सभी घरों में समान रूप से पानी आपूर्ति हो सके। उन्होने निगम के पेयजल विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि वे इसकी जांच करें, मुनादी कराकर लोगों से टूल्लू पम्प हटाने को कहें, यदि उनके द्वारा इसके बावजूद भी टूल्लू पम्प नहीं हटाए जाते तो जिन लोगों द्वारा टूल्लू पम्प लगाए जा रहे हैं, उनके पम्पों को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने निर्धारित स्थानों पर कंट्रोल वाल व रेड्यूसर लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि पानी की सप्लाई सभी घरों में समान रूप से हो सके। महापौर प्रसाद ने बस्ती का भ्रमण कर साफ-सफाई कार्यो का निरीक्षण किया तथा बेहतर स्वच्छता कायो के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घंटाघर का किया निरीक्षण - महापौर राजकिशोर प्रसाद ने घंटाघर पहुंचकर वहाँ की साफ-सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का सघन रूप से निरीक्षण किया। घंटाघर परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई करने तथा निगम द्वारा स्थापित किए गए सेल्फी प्वाइंट '' आई लव कोरबा '' की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर घंटाघर व्यवसायियों द्वारा घंटाघर परिसर में यूरिनल व शौचालय की आवश्यकता का आग्रह करते हुए इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने की मांग की, जिस पर महापौर प्रसाद ने घंटाघर परिसर के उपयुक्त स्थल पर यूरिनल शौचालय निर्माण किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

बस्तर फाइटर्स की 280 महिला नव आरक्षकों का प्रशिक्षण पूरा

■ आईजी ने मेडल देकर किया सम्मानित

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज बस्तर फाइटर्स महिलाओं का पुलिस सेवा हेतु बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय पीटीएस में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया,जिसमें नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बस्तर फाइटर्स की महिला नव आरक्षकों को उनके उत्कृष्ट ट्रेनिंग के लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सल मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। वहीं अब पुलिस सेवा में महिला बस्तर फाइटर्स को लेकर भी बस्तर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित होगा। बस्तर में महिला नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए पुलिस विभाग ने बस्तर क्षेत्र में ही

महिलाओं को तैयार किया है और बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों से महिलाओं को पुलिस सेवा में जाने के लिए भर्ती अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान आईजी ओपी पाल ने कहा कि इन महिला नव आरक्षक की परेड का स्तर इनकी ट्रेनिंग की मेहनत और ऊर्जा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब यह फील्ड में जाएंगी तो बेहतरीन काम करके नक्सलवाद का खात्मा करेंगी।

बस्तर के 7 जिलों से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने राजनांदगांव के पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर 280 महिला नव आरक्षकों यहां से पास आउट किया है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला आरक्षक कुमारी दामिनी उईके ने कहा कि पुलिस विभाग में आना मेरा सपना रहा है, आज ट्रेनिंग पूरी करने पर बेहद खुशी हो रही है।

राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 280 महिला बस्तर फाइटर्स नवा रक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पीटीएस में हुए इस दीक्षांत समारोह में इन बस्तर महिला फाइटर्स ने अपने दमखम और शौर्य को प्रदर्शित किया राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से दक्ष होकर अब यह महिला बस्तर फाइटर्स नक्सलियों से मुकाबला करने में पूरी तरह से तैयार हैं। इस दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस परिवार के लोग शामिल हुए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ममता सरकार पर गृह मंत्रालय ने राशि चुकाने का दबाव बढ़ाया

नईदिल्ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफे की मांग की है। ममता की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों से बकाया राशि मांगने के लिए राज्य पर दबाव बढ़ाया। मंत्रालय ने एक लिखित संदेश में कहा है कि बकाया के कारण मूल राशि पर जुर्माना लगाया गया है। परिणामस्वरूप अब तक करीब 1852 करोड़ रुपये का निस्तारण होना शेष है। गृह विभाग के एक सूत्र ने बताया कि राज्य पर केंद्र की बड़ी रकम बकाया है। यह पैसा उन्होंने लंबे समय से रोक रखा है। उस लिहाज से मंत्रालय द्वारा मांगी गई राशि बहुत कम है। चुनाव, कानून व्यवस्था सहित कई कारणों से केंद्रीय बलों को राज्यों में तैनात किया जाता है। लगभग सभी मामलों में केंद्र राज्यों से बलों के लिए एक निश्चित राशि की मांग करता है। मंत्रालय की ओर से राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पिछले साल 30 जून तक राज्य पर इस क्षेत्र का करीब 1806 करोड़ बकाया है।

सचिन पायलट के आरोपों पर वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलीभगत के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि दूध और नींबू का रस एक साथ नहीं हो सकते। वसुंधरा राजे ने कहा कि साजिश के तहत झूठ फैलाया जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए और सचिन पायलट का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए राजे ने कहा कि झूठे आरोप लगाए बिना कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता। पिछले हफ्ते, भाजपा शासन के दौरान भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर अशोक गहलोत सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ अपने दिन भर के उपवास की घोषणा करते हुए, पायलट ने कहा था कि कांग्रेस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए अन्यथा लोग मान लेंगे कि कोई मिलीभगत है। उसी के बारे में बोलते हुए, राजे ने कहा कि कई लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं कि वे मिलीभगत कर रहे हैं। राजे ने पूछा कि उनकी विचारधारा और सिद्धांतों से मेल नहीं खाने वालों के साथ सांठगांठ कैसे संभव है।

देश में जो हो रहा है उससे हम चिंतित, दबाव में हैं एजेंसियां

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि आज देश में जो हो रहा है उससे हम चिंतित हैं। एजेंसियां दबाव में हैं। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर देश दबाव में चलेगा तो यह देशहित में नहीं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम राज्य में फिर से सरकार बनाएंगे। साथ ही सीथ गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी की सभी ताकतें राजस्थान आएंगी। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें (बीजेपी को) बंगाल में हराया और अब उन्हें (बीजेपी) यहां बड़ी हार मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे राजनीति से विचलित नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने आगे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से मेहनगाई राहत शिविरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट नहीं : ओएसडी

चंडीगढ़। पिछले सालों में रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले के तमाम आरोप लगाए गए। इन्हीं आरोपों के बीच खबर आई कि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि डीएलएफ लैंड डील में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब इसी कांग्रेस दावा कर रही है कि इस मामले में वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टक के ओएसडी जवाहर यादव का दावा इससे बिल्कुल विपरित है। जवाहर यादव ने साफ तौर पर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। अपने बयान में जवाहर यादव ने कहा कि जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जांच जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जांच पूरी होने के बाद हम आपको परिणाम के बारे में बताएंगे।

एनसीपी में जो चल रहा उनका आतंरिक मामला है : राउत

मुंबई। मुंबई में उद्योगपति गौतम अडानी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात के कुछ घंटे बाद शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने उनसे उनके आवास पर मुलाकात की। राउत ने पवार से दक्षिण मुंबई में उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की, लेकिन दोनों राजनीतिक नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं है। संजय राउत ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी बैठकें होती रहती हैं। संजय राउत ने कहा कि मैंने शुक्रवार को शरद पावर साहब से मुलाकात की और हमारे बीच बहुत से विषय एवं राज्य में जो चल रहा है उस पर चर्चा हुई। एनसीपी में जो चल रहा है यह उनका आंतरिक मामला है। इससे पहले दिन में अडानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और यह मुलाकात करीब दो घंटे तक चली।

भारत की ओर उम्मीदों से देख रही दुनिया, सिविल सर्विस डे में बोले प्रधानमंत्री

चूक हुई तो लुट जाएगा देश का धन : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां सरकारी धन का इस्तेमाल देश के विकास में कर रही हैं या अपने दल के विस्तार में या फिर वोट बैंक बनाने के प्रयास में वह उसे लुटा रही हैं। लोक सेवा दिवस पर राजधानी में लोक सेवकों को संबोधित करते हुए मोदी ने उनसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो देश का धन लुट जाएगा, करदाताओं के पैसे बर्बाद हो जाएंगे और युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे।

पीएम मोदी ने दिए उत्कृष्टता पुरस्कार

इस अवसर पर पीएम मोदी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कामकाज के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस?कार भी प्रदान किए। ये पुरस?कार नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से जिलों और संगठनों को असाधारण प्रयासों और नई पहलों के लिए दिये जाते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लोक सेवकों के छोटे से छोटे फैसलों का आधार भी देश हित होना चाहिए।

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर दल की अपनी विचारधारा होती है और संविधान ने हर दल को यह अधिकार भी दिया है लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ सवालों का अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा।

धन के खर्च पर रखें नजर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है क्या वह करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है? उसका उपयोग कहां हो रहा है ? यह आप लोगों को देखना ही होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या देश के विकास में उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वह अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है।

फैसले से पहले सवालों के बारे में सोंचे

पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे। उनकी अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरना है। नहीं तो देश का धन लुट जाएगा, करदाताओं के पैसा बर्बाद हो जाएगा और देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अमृत काल का भी उल्लेख किया और कहा कि मौजूदा दौर में उनकी (लोकसेवकों की) भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है।

काली कमाई का रास्ता रोकें

पीएम मोदी ने कहा, वह राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है? वह राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सब को पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है? राजनीतिक दल नीतियों में कहीं इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा है ताकि उसके आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बनें ?

भारत से बढ़ी है दुनिया की अपेक्षाएं

पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व की भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यह कह रही हैं कि भारत का समय आ गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह ऐसा समय है जब उन्हें एक भी पल नहीं गंवाना है।

सूडान में फंसे भारतीयों की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीयों से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वायु सेना और नौ सेना के प्रमुख, विदेश और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ राजनयिक डिजिटल तरीके से शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्तमान के गुयाना के दौरे पर हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम सहित देश के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा में एक भारतीय समेत 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भारत ने गुरुवार को कहा था कि सूडान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और वह भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब एवं मिस्र सहित विभिन्न देशों के साथ करीबी समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नयी दिल्ली में कहा था कि सूडान में चार-पांच दिन बाद भी संघर्ष कम नहीं हुआ है। लड़ाई जारी है और स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसे में हम भारतीयों से आग्रह करते हैं कि वे जहां हैं, वहीं रहें और बाहर न निकलें। उन्होंने कहा था, हम सूडान के घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर रख रहे हैं। सूडान में भारतीय दूतावास औपचारिक, अनौपचारिक माध्यम से भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। यह संघर्ष देश के सैन्य नेतृत्व के भीतर ताकत के संघर्ष का सीधा परिणाम है। देश में सूडान की नियमित सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नामक अर्द्धसैन्य बल के बीच टकराव के कारण यह हिंसा हुई है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती

2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करें

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ समय ही बाकी रह गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं। तमाम चुनावी मुद्दों के बीच राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। दरअसल, राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस की 'जय भारत' चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि पीएम मोदी साल 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करें।

इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की भी मांग की है। राहुल गांधी का कहना है कि साल 2011 में यूपीए सरकार में हुई जाति जनगणना के आंकड़ों को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। राहुल के अनुसार, अगर पीएम मोदी ऐसा नहीं करते हैं तो यह ओबीसी का अपमान है। उन्होंने कोलार में कहा कि पीएम मोदी ओबीसी की बात करते हैं तो वह उस आंकड़े को जारी क्यों नहीं करते हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि देश में कितने दलित, ओबीसी और आदिवासी हैं।

राहुल ने आगे कहा कि जातीय जनगणना हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने का आधार है, यह वंचितों का आधार है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में केवल 7 फीसदी सचिव ओबीसी, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसलिए यूपीए सरकार में हुई जाति जनगणना के आंकड़े को पीएम मोदी को सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह ओबीसी का अपमान होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि सभी को देश के विकास का हिस्सा बनाना है तो हर समुदाय की आबादी का पता लगाया जाना जरूरी है।

कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी को पूरे बहुमत से विजयी बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी 40 फीसदी कमीशन वाले पैसे से आपकी सरकार को चुराने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन अब इनके भ्रष्टाचार को मौका नहीं देना है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया है।

बांटते-बांटते कांग्रेस खुद भी इतने बंट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं : नड्डा

बेंगलुरु। कर्नाटक ने बीदर में जेपी नड्डा ने श्री रामकृष्ण आश्रम का दौरा किया। इस दौरान नड्डा ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि बांटते-बांटते वह खुद भी इतने बंट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस को हटे 60 वर्ष हो गए..जो पांव उखड़े तो उखड़े ही रह गए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल में लगभग साढ़े 8 साल से सरकार से बाहर है। न वो तेलंगाना में रहे और न ही आंध्र प्रदेश में रहे। जब कांग्रेस और जेडीएस सरकार आती है और जब कांग्रेस-जेडीएस भाई-भाई की सरकार आती है तो भारत की योजना कर्नाटक की जनता को मिलने से रोक दिया जाता है। नड्डा ने यह भी कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए रास्ते पर चलना है। उनका महान जीवन अपने आप में एक सीख रहा है। हमें अपने जीवन को आलोकित करने के लिए उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

पंजाब के खिलाफ आज मुंबई का मुकाबला

मुंबई। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत की लय हासिल कर ली है और वह पंजाब किंग्स के खिलाफ शनिवार (22 अप्रैल) को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में मैदान पर उतरेगी। मुंबई में पहले दोनों मैच गंवाकर लचर शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद उसने दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद को हराया तथा अभी वह अंक तालिका में छठे स्थान पर है। दूसरी तरफ पंजाब अंक तालिका में सातवें स्थान पर है।

पंजाब किंग्स को नियमित कप्तान शिखर धवन की कमी खल रही है जो चोटिल होने के कारण पिछले दो मैचों में नहीं खेल पाए थे और उनका मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैच में भी खेलना संदिग्ध है। पंजाब के लिए धवन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने शुरुआती चार मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए, लेकिन इसके बाद कंधे की चोट के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा। पंजाब ने अभी तक छह मैच खेले हैं जिनमें से उसे तीन मैचों में जीत मिली लेकिन उसे पिछले चार में से तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को भी अगर मुंबई के बल्लेबाजों को रोकना है तो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा अर्शदीप सिंह, कैगिसो रबाडा और कुरेन की मुंबई के बल्लेबाजों के सामने कड़ी परीक्षा होगी, रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मुंबई को अच्छी शुरुआत दिलाई है। कैमरन ग्रीन और टिम डेविड ने पिछले तीन मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन टीम के लिए अब भी मध्यक्रम के प्रमुख बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का पूरी तरह फॉर्म में नहीं लौट पाना चिंता का विषय है। गेंदबाजी में मुंबई को फिर से अपने प्रमुख गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बिना उतरना पड़ सकता है। वह मुंबई के पहले मैच के बाद नहीं खेल पाए हैं और अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 23 अंक मजबूत, निफ्टी में कोई खास बदलाव नहीं

नईदिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन (शुक्रवार) शेयर बाजार में हल्की तेजी देखी गई। आज के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 23 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में 0.40 अंकों की मामूली गिरावट दर्ज की गई और कारोबार के अंत में निफ्टी 17,624.05 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 22.71 अंक यानी 0.04 फीसदी मजबूत होकर 59,655.06 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 59,781.36 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 59,412.81 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसमें 0.40 अंकों की मामूली गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी कारोबार के अंत में 17,624.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 17,663.20 की उंचाई तक गया और नीचे में 17,553.95 तक आया।

प्रमुख बंदरगाहों पर बढ़ी माल ढुलाई

नईदिल्ली। देश के प्रमुख बंदरगाहों ने 2022-23 में 79.5 करोड़ टन माल संभाला, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सचिव सुधांश पंत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 5,000 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ पोत परिवहन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय 3,700 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने (मौद्रिकरण) के लक्ष्य को पार कर लिया है। पंत ने यह भी कहा कि अगले सप्ताह बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाहों को हरा-भरा बनाने के लिए 'ग्रीन बंदरगाह' की शुरुआत करेंगे। पंत ने कहा, 'हमारे प्रमुख बंदरगाहों ने बीते वित्त वर्ष में अब तक सर्वाधिक 79.5 करोड़ टन माल को संभाला है। यह पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी अधिक है।'

प्राइवेट क्षेत्र का पहला कॉर्गो टर्मिनल रेवाड़ी में शुरू

नईदिल्ली। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसी) ने शनिवार को रेवाड़ी गति शक्ति कॉर्गो टर्मिनल (जीसीटी) से कामकाज शुरू कर दिया है। जीसीटी सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) मॉडल पर बना है, जिसमें पूरा निवेश निजी कारोबारियों ने किया है और इसमें भारतीय रेलवे से शून्य राजस्व साझेदारी है। हरियाणा में 8 करोड़ रुपये का जीसीटी पूरी तरह से कंटेनर ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, जो वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के न्यू रेवाड़ी स्टेशन की लाइन 10 के किनारे है। इसका परिचालन प्रिस्टाइन मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क द्वारा होगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकोर) और शिपिंग दिग्गज डीपी वर्ल्ड के साथ दौड़ में इसे प्रिस्टाइन ने प्राप्त किया।

इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होम लोन की डिमांड घटी

नई दिल्ली। बढ़ती ब्याज दरें अब उपभोक्ताओं को भी चुभने लगी हैं। इस बात की तस्दीक करते हैं दिसंबर तिमाही के आंकड़े। पिछले साल से तुलना करें तो दिसंबर तिमाही में होम लोन की डिमांड और वितरण में गिरावट आई है। क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में होम लोन के वितरण में 6% की गिरावट आई है। वहीं होम लोन से जुड़ी पूछताछ में 1% की कमी दर्ज हुई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बेंचमार्क रीपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स (100 बीपीएस = 1 पर्सेंटेज पॉइंट) का इजाफा कर चुका है। इस भार को बैंकों ने धीरे-धीरे खरीदारों तक पहुंचाया है। इस वक्त न्यूनतम होम लोन रेट 8.5% है, जबकि एक साल पहले यह 6.5% था। रिटेल कर्ज, जिससे कि हाल की तिमाहियों में बैंकों का क्रेडिट बढ़ा है।

भारत की दूरसंचार में अग्रणी भूमिका निभाने की तैयारी

प्रभात सिन्हा

हमारे देश में अक्तूबर 2022 को 5जी सेवाओं का उद्घाटन किया गया और देशभर में इन सेवाओं का विस्तार 2024 के अंत तक हो जायेगा। इस विकास की प्रक्रिया में विशेषज्ञों ने बेहतर तकनीक विकसित कर देश को दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। इसी आधार पर भारत वैश्विक वायरलेस मानक मोबाइल नेटवर्क की 6वीं पीढ़ी में अग्रणी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। भारत ने 6जी से संबंधित तकनीक के 127 पेटेंट हासिल कर लिये हैं, जिन्हें अमेरिका सहित कई विकसित देश साझा करना चाहते हैं।

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावृत किये गये विजन दस्तावेज के अनुसार, भारत 2030 तक हाई स्पीड 6जी संचार सेवाओं को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 1जी की शुरुआत 1980 में हुई थी, जिससे एनालॉग वॉयस मिला। 1990 से शुरू हुए 2जी से डिजिटल वॉयस ईजाद हुआ, जिसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) तकनीक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2000 में 3जी का प्रारंभ हुआ था, जहां से मोबाइल डेटा मिलने लगा। 2010 में 4जी सेवाओं की शुरुआत हुई, जिससे प्रदत्त एलटीइ तकनीक से मोबाइल ब्रॉडबैंड युग का आगाज हुआ।

वायरलेस मानक मोबाइल नेटवर्क का हालिया संस्करण 5जी नयी तकनीक ऑर्थोगोनल फ्रक्वेंसीडिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (ओएफडीएम) पर आधारित है, जो हस्तक्षेप को कम करने के लिए विविध चैनलों में डिजिटल सिग्नल को संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें ओएफडीएम तकनीक के साथ ही न्यू रेडियो (एनआर) एयर इंटरफेस, सब-6 गिगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव जैसी व्यापक बैंडविड्थ तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है।

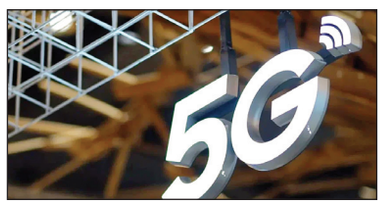

5जी के प्रसार के लिए कम शक्ति वाले सेलुलर रेडियो एक्सेस नोड, स्मॉल सेल का भी उपयोग होता है। उच्च आवृत्तियों के कारण 5जी की रेडियो तरंगों का प्रसार लंबी दूरी तक संभव नहीं हो पाता है, इसलिए स्मॉल सेल का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्यादा गति प्राप्त करने के लिए 5जी नेटवर्क में बहुत सारी ऑपरेटिंग आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे मिलीमीटर वेव बैंड कहते हैं। अभी अवधारणा चरण में होने के बावजूद 6जी पहले से ही एकीकृत मानव-मशीन और मशीन-टू-मशीन कनेक्टिविटी के सिद्धांतों के साथ लोकप्रिय हो रहा है। संभावना है कि 6जी नेटवर्क अप्रयुक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी में संचालित होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग कर 5जी नेटवर्क से कई गुना तेज गति से लो-लेटेंसी संचार संभव हो पायेगा। काफी तेज गति होने के कारण यह समय और भौतिक बाधाओं को नगण्य बना कर आवश्यक जानकारी, संसाधनों (आभासी और भौतिक दोनों) और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को आसान बना देगा। उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र में गहन अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्योग संबंधित वार्तालाप और आभासी यात्राओं का अनुभव करा पायेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आदि तकनीकों के प्रयोग से कृषि, स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में तेज विकास संभव हो पायेगा। साथ ही, क्वांटम सेंसिंग, संचार, सुरक्षा और कंप्यूटिंग की विशेषताओं और क्षमता को समझने के लिए क्वांटम तकनीकों पर अनुसंधान में भी 6जी से काफी लाभ होगा। इसके प्रचलन से पृथ्वी के गहरे तल में उपग्रहों और एचएपीएस जैसी नयी तकनीकों की प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिसके कारण गैर-स्थलीय वायरलेस नेटवर्क जहाजों और विमानों के अलावा स्थलीय तथा कम सेवा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वव्यापी उपलब्धता के साथ एकीकृत हो जायेंगे।

6जी परियोजना के तहत नौ साल के कार्यकाल (2022-2031) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाने की तैयारी है, जिसको तीन चरणों में बांटा गया है। चार वर्षों के पहले चरण का मुख्य उद्देश्य अनुदान जुटाना होगा। दूसरा चरण वर्ष 4-7 तक होगा, जबकि तीसरा चरण वर्ष 7-9 तक होगा।

रूस, चीन और भारत के आपसी संबंधों की हिचक

राजेश बादल

भारत, चीन और रूस। तीन बड़े एशियाई देश। साम्यवाद छोड़कर अधिनायकवादी रास्ते पर चल रहे चीन और रूस इन दिनों पश्चिम और यूरोप से कमोबेश सीधे-सीधे टकराव की मुद्रा में हैं। भारत वैसे तो यूक्रेन के साथ रूस की जंग में इन दोनों राष्ट्रों के साथ खड़ा नजर आता है लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं इसलिए एशिया की यह तीन बड़ी ताकतें एक मंच पर एकसाथ अपनी-अपनी हिचक या द्वंद्व के साथ उपस्थित हैं। इस हिचक के कारण ऐतिहासिक हैं और अफसोस है कि उन कारणों पर तीनों मुल्क गंभीरता से विचार नहीं करना चाहते। इसका असर रूस और चीन की सेहत पर अधिक नहीं पड़ रहा है, पर भारत के लिए यह चिंता में डालने वाली वजह हो सकती है। एक तो भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप और दूसरा विकास की धीमी रफ्तार। कोई नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में वह समय कब आएगा जब वह रूस और चीन के साथ विकास तथा तकनीक में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सकेगा? जहां तक भारत और चीन की बात है तो उसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। अंग्रजों की ओर से निर्धारित सीमा संबंधी मैकमोहन लाइन के बाद 1959 से जो विवाद शुरू हुआ है, वह अभी तक जारी है। चीन उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने पक्ष में हरदम उसने बहाने ही बनाए हैं। चाहे तिब्बत या अरुणाचल का मामला हो अथवा भूटान, म्यांमार या नेपाल से सटी सीमा पर तनाव की स्थिति हो। असल में सन बासठ में हुई जंग ने अविश्वास के इतने गहरे बीज बो दिए हैं कि वे सदियों तक बने रहेंगे और भारत को दु:ख पहुंचाते रहेंगे। चीन की विस्तारवादी नीति शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा भारत पर तीन बार युद्ध थोपने वाले पाकिस्तान को उसका खुला समर्थन है। पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर का एक बड़ा इलाका चीन को उपहार में सौंप दिया था। चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना नहीं चाहता, वह इस पर कोई उदार रवैया भी नहीं अपनाना चाहता। इन कारणों के अलावा भी भारत की रूस-यूक्रेन जंग में चीन के साथ खड़े होने की अपनी हिचक है। रूस 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में खुलकर भारत के साथ आया था। चीन तब पाकिस्तान के पाले में था। इसके अलावा एशिया की दोनों बड़ी ताकतों से बैर करके वह नहीं चल पाएगा। अमेरिका व्यापारी देश है। बीते सत्तर साल में उसने भारत की कभी खुलकर मदद नहीं की है। जहां उसका स्वार्थ आड़े आया है ,वहीं वह भारत के साथ दिखाई दिया है। भारत यह अपेक्षा तो कर ही सकता है कि भविष्य में यदि चीन के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति बनती है तो रूस बीच-बचाव के लिए आगे आ सकता है। मौजूदा जंग में भारत यदि रूस के पक्ष में संग खड़ा नजर आया है तो उसके पीछे विशुद्ध भारतीय हित हैं, न कि लोकतंत्र की नैतिकता। चीन की भी भारत और रूस के साथ अपनी हिचक है। भारत के अमेरिका के साथ मौजूदा रिश्ते उतने तनावपूर्ण नहीं हैं, जितने चीन के हैं। यह बात चीन को खलती है लेकिन एशिया में वह भारत की उपेक्षा करके भी नहीं चल सकता। वह भारत के साथ रिश्तों में ईमानदार नहीं है, लेकिन चाहता है कि भारत उसके साथ एकतरफा व्यापार करता रहे। आज भी भारत में उसके निर्यात का आकार, आयात से कई गुना बड़ा है। उसके वित्तीय हित सधते हैं क्योंकि लगभग डेढ़ सौ करोड़ की आबादी वाले देश का बाजार वह यूं ही नहीं छोड़ सकता इसलिए पाकिस्तान का साथ देकर वह भारत को सिर्फ असहज तथा परेशान रखना चाहता है। इसी तरह वह रूस का भी सौ फीसदी खरा दोस्त नहीं है। भले ही एक जमाने में रूस ने उसे साम्यवाद की परिभाषा सिखाई हो और जापान के हमले के समय अपनी वायुसेना मदद के लिए भेजी हो। वह रूस से जमीन के लिए जंग भी लड़ चुका है।

कर्तव्यबोध से भरा भारत

प्रो. संजय द्विवेदी

आजादी के अमृत महोत्सव से अमृतकाल की यात्रा में देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह आत्मविश्वास 2014 के बाद हर भारतवासी में आया है जो कुछ समय पहले तक अवसाद और निराशा से घिरा था। भरोसा जगाने वाला यह समय हमें जगा कर कुछ कह गया और लोग राष्ट्रनिर्माण में अपनी भूमिका को रेखांकित और पुर्नपारिभाषित करने लगे। इस देश का कुछ नहीं हो सकता से यह देश सब कुछ कर सकता है तक हम पहुंचे हैं। यह साधारण नहीं है कि कल तक राजनीतिक-प्रशासनिक जड़ता, निर्णयहीनता, नकारात्मक राजनीति और अवसाद से घिरा भारत अवसरों के जनतंत्र में बदलता दिख रहा है। यह आकांक्षावान भारत है, उम्मीदों से घिरा भारत है, अपने सपनों की ओर दौड़ लगाता भारत है। लक्ष्यनिष्ठ भारत है, कर्तव्यनिष्ठ भारत है। यह सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ने वाला नहीं बल्कि कर्तव्यबोध से भरा भारत है।

ये वक्त हमारा है-

सही मायनों में यह भारत का समय है। भारत में बैठकर शायद कम महसूस हो किंतु दुनिया के ताकतवर देशों में जाकर भारत की शक्ति और उसके बारे में की जा रही बातें महसूसी जा सकती हैं। सांप-संपेरों के देश की कहानियां अब पुरानी बातें हैं। भारत पांचवीं बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में विश्व मंच पर अपनी गाथा स्वयं कह रहा है। अर्थव्यवस्था,भू-राजनीति, कूटनीति, डिजिटलीकरण से लेकर मनोरंजन के मंच पर सफलता की कहानियां कह रहा है। सबसे ज्यादा आबादी के साथ हम सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश भी बन गए हैं, जिसकी क्षमताओं का दोहन होना अभी शेष है। भारत के 1 अरब लोग नौजवान यानि 35 साल से कम आयु के हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा प्रयासों, कोविड के विरुद्ध जुटाई गई व्यवस्थाएं, जी-20 के अध्यक्ष के नाते मिले अवसर, जीवंत लोकतंत्र, स्वतंत्र मीडिया हमें खास बनाते हैं। चुनौतियों से जूझने की क्षमता भारत दिखा चुका है। संकटों से पार पाने की संकल्प शक्ति वह व्यक्त कर चुका है। अब बात है उसके सर्वश्रेष्ठ होने की। अव्वल होने की। दुनिया को कुछ देने की।

नए भारत के शिल्पकार

निश्चित यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। नौकरशाही की जड़ता, राजनीति के सीमित पांच साला लक्ष्य, समाज में फैली गैरबराबरी और असमानता, क्षेत्रीयता,जातीयता की भावनाओं में बंटा समाज लक्ष्यों में बाधक था और आज भी कमोबेश ये संकट बने हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मंच पर आगमन के साथ सारा कुछ बदल गया है। आम आदमी सरकारी प्रयासों के साथ देश के व्यापक लोकतंत्रीकरण में सहायक बना है। भारत सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साफ्ट पावर में भी अग्रणी बना है। स्थान-स्थान पर भारतीय प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें सम्मानित करने का क्रम भी जारी है जिससे भारत की आत्मा जाग रही है। आप पिछले कुछ सालों में पद्म सम्मानों की सूची का अवलोकन करें तो आपका मन गर्व से भर जाएगा और एक नए भारत को बनता हुआ देख पाएंगें। दिल्ली से निकल देश की संभावनाएं छोटे शहरों और गांवों तक ले जाने के व्यापक प्रयास सब तरफ दिखने लगे हैं। छोटे शहर अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं, गांव संसाधनों का केंद्र बनने के लिए व्यग्र हैं। नीतिगत फैसलों में गति लाकर देश का चेहरा बदलने के ये प्रयास साधारण नहीं हैं। प्रधानमंत्री इस परिघटना को बहुत उम्मीद से देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि- %%भारत ने आज जो कुछ हासिल किया है, वह हमारे लोकतंत्र की ताकत, हमारे संस्थानों की ताकत की वजह से संभव हो पाया है। दुनिया देख सकती है कि भारत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुयी सरकार निर्णायक फैसले ले रही है। हमने दुनिया को दिखा दिया है लोकतंत्र कितना फलदायी हो सकता है।

नीयत से बदलती नीतियां-

परिर्वतन को रोका नहीं जा सकता। यह नैसर्गिक है। किंतु परिर्वतन या बदलाव की दिशा जरूर तय की जा सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से किए गए काम हमेशा परिणाम देते हैं और उनसे समाज को दिशा मिलती है। बहुत पुरातन और गौरवशाली राष्ट्र होने के बाद भी हमें अपनी कमियों से लगातार आक्रमण, गुलामी और संघर्ष का समय देखना पड़ा। बावजूद इसके 'चिति' स्वतंत्र रही। राज और समाज की दूरी ने समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को चुकने नहीं दिया। अत्याचार और विदेशी शासकों के दमन के विरूद्ध भारत का संघर्ष जारी रहा। 1947 के बाद स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, भारतीय भाषाओं और भारतीय जन के सम्मान का जो समय प्रारंभ होना था वह नहीं हो पाया। लोकसेवक, जनसेवक शासक बन बैठे और उनकी मानसिकता वही थी, जो विरासत में मिली थी। इसने देश के स्वाभिमान को जगने नहीं दिया। लंबे समय के बाद अच्छे काम पर भरोसा करते हुए जनमानस का जागरण हुआ है। अपने वर्तमान नेतृत्व के प्रति समाज का असंदिग्ध विश्वास है और उनकी क्षमताओं पर नाज। आजादी के बाद हर सरकार और उसके प्रधान ने निश्चित ही कुछ जोड़ा है। देश ने प्रगति और विकास के नए सोपान तय किए हैं। किंतु भ्रष्टाचार, दिशाहीनता, राजनीतिक निर्णयों में हानि-लाभ के विचार ने उसके संपूर्ण लाभ से वंचित किया। सामान्य जन के विकास योजनाओं के एक रुपए में पचासी पैसे के डूब जाने की कहानियां हमने खूब सुनी हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री की विवशता भी प्रकट होती है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का घुन अंदर तक प्रवेश कर चुका है। डिजिटलीकरण ने इस पर न सिर्फ अंकुश लगाया है, वरन लोगों को राहत दी है। सुशासन के लक्ष्य इसी पारदर्शिता से पाए जा सकते हैं। 2015 से 2017 के बीच 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। भारत आज यूरोप और अमेरीका की तुलना में 11 गुना ज्यादा डिजिटल पेमेंट करता है। आयुष्मान भारत ने 31 करोड़ भारतीयों के लिए मुफ्त कैंसर जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की है। यह एक साधारण आंकड़ा भर नहीं है। नई व्यवस्था में स्वयं सहायता समूहों में लगभग 9 करोड़ महिलाओं को 32 अरब डालर (2.6 लाख करोड़ रूपए) की उधार सुविधा दी जा रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। इसी संदर्भ में गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं- 2014 के पहले देश के 60 करोड़ लोग सपना नहीं देख सकते थे। मोदीजी ने उनके जीवन में उम्मीद जगाई है और उनमें महत्वाकांक्षाएं पैदा की हैं। भारत जब आजादी का शताब्दी उत्सव मना रहा होगा तो वह हर क्षेत्र में नंबर-1 होगा।

उम्मीदें जगाता नया भारत

नया भारत अपने सपनों में रंग भरने के लिए चल पड़ा है। भारत सरकार की विकास योजनाओं और उसके संकल्पों का चतुर्दिक असर दिखने लगा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक उत्साह से भरे हिंदुस्तानी दिखने लगे हैं। जाति, पंथ, भाषावाद, क्षेत्रीयता की बाधाओं को तोड़ता नया भारत बुलंदियों की ओर है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की सुनें तो 2070 तक हम बाकी दुनिया को 20-30 प्रतिशत वर्कफोर्स उपलब्ध करवा सकते हैं और यह बड़ा मौका है। ऐसे अनेक विचार भारत की संभावनों को बता रहे हैं। अपनी अनेक जटिल समस्याओं से जूझता, उनके समाधान खोजता भारत अपना पुनर्अविष्कार कर रहा है। जड़ों से जुड़े रहकर भी वह वैश्विक बनना चाहता है। उसकी सोच और यात्रा ग्लोबल नागरिक गढ़ने की है। यह वैश्विक चेतना ही उसे समावेशी, सरोकारी, आत्मीय और लोकतांत्रिक बना रही है। लोगों का स्वीकार और उनके सुख का विस्तार भारत की संस्कृति रही है। वह अतिथि देवो भव: को मानता है और आंक्राताओं का प्रतिकार भी करना चाहता है। अपनी परंपरा से जुड़कर वैश्विक सुख, शांति और साफ्टपावर का केंद्र भी बनना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री इसीलिए भरोसे से यह कह पाते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। यह समय देश की रचनात्मकता, विश्वसनीयता और क्षमता को प्रकट करने वाला है। यही समय भारत का भी है और भारतबोध का भी। आइए इन सपनों को पूरा करने के लिए भागीरथ प्रयत्नों में अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। हमारे छोटे किंतु समन्वित प्रयासों से भारत मां फिर से जगद्गुरु के आसन पर आसीन होंगीं और अपने आशीष की हम सब पर वर्षा करेंगीं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

शाण्डिल्यापोनषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

इस समय ज्योति रूप समस्त बाहरी विषयों से विहीन एवं दीप्तिमान् जो तत्त्व प्रकाशित हो रहा है, वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय होता है। है शाण्डिल्य ! इस प्रकार तुम्हें जानना चाहिए।

योगी साधक दोनों नेत्रों की पुतलियों को ज्योति से जोड़कर दोनों भौंहों को कुछ ऊँचा रखता है। यह साधक के प्रारम्भिक अभ्यास का मार्ग है और इससे क्षणमात्र में ही उन्मनी स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, उससे वह उन्मनी दशा को प्राप्त करता है, फिर उसे योग- निद्रा की प्राप्ति हो जाती है। जिस साधक को योग निद्रा की प्राप्ति हो, वह योगी फिर काल के वश में नहीं होता।

इस कारण हे शाण्डिल्य ! शक्ति के बीच में मन को केन्द्रित करो। शक्ति को मन के अन्दर गतिशील रखकर तुम मन के द्वारा मन को ही देखो तथा सुखी-समुन्नत जीवन व्यतीत करो। ऐसे ही (चैतन्य) आकाश के बीच में आत्मा को स्थित करके तथा आत्मा के मध्य में (चैतन्य) आकाश को प्रतिष्ठित देखना चाहिए। इसके पश्चात् सभी को (चैतन्य) आकाशमय करके, ऐसा ध्यान करें कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। योगी को बाह्यजगत् की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार अपने भीतर की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इस तरह समस्त प्रकार की चिन्ताओं का परित्याग करके मात्र चैतन्य स्वरूप हो जाना चाहिए। जिस तरह से कपूर अग्नि में तथा नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी तरह से ध्यानस्थ हुए योगी का मन परम तत्त्व में विलीन हो जाता है।

जो भी कुछ जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है, उसका जो ज्ञान है, उसे ही मन कहते हैं। ज्ञान एवं ज्ञेय सभी कुछ एक ही साथ विनष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं है। ज्ञेय वस्तु का परित्याग कर देने से मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है और जब मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है, तब कैवल्य ही कैवल्य शेष रह जाता है।

हे मुनीश्वर! चित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं- 1. योग और 2. ज्ञान योग अर्थात् चित्त की वृत्तियों का शमन करना तथा ज्ञान अर्थात् वस्तु के तत्त्व को यथार्थ रूप में देखना।

क्रमश:...

विश्व पृथ्वी दिवस : प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर

अनु साइकॉम

क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कैसे प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? चाहे आप जंगल में हों या रेगिस्तान में, आप एक पारिस्थितिकी तंत्र से घिरे हुए है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन के एक बड़े, जटिल जाल की तरह है, जहां पौधे, जानवर और पर्यावरण सभी चीजों को संतुलन में रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह एक समुदाय की तरह है, जहां प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका होती है और जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है।

यह विभिन्न तत्वों का एक नाजुक संतुलन है जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए सामंजस्य के साथ काम करते हैं। हरे-भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर विशाल महासागरों तक, शुष्क रेगिस्तानों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक, पारिस्थितिक तंत्र पूरे ग्रह में वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला में मौजूद हैं। 'इकोसिस्टम शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है-ओइकोस जिसका अर्थ है घर या रहने का स्थान और सिस्टेमा का अर्थ है सिस्टम।

पारिस्थितिकी तंत्र पर हमारी निर्भरता

पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह हमारे लिए खाद्य, पानी और अन्य उपयोगी सामग्री को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही यह हमें आकाशमंडल की संरक्षा भी प्रदान करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र से, मानव जैविक और अजैविक घटकों से बहुत सारे लाभ प्राप्त करता है। इन लाभों को सामूहिक मूल रूप से पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता इन्हीं सेवाओं पर निर्भर करती है। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है-प्रावधानीकरण, विनियमन, सांस्कृतिक और सहायक सेवाएं। प्रोविजनिंग या प्रावधानीकरण सेवाओं में वो चीजें हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती हैं जिनकी हमें जीवित रहने और अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए जरूरत होती है, जैसे भोजन, पानी, और संसाधन जैसे लकड़ी और खनिज आदि।

इसी तरह विनियमन सेवाएं वे सेवाएं हैं जो हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने और ठीक से काम करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, उनमें जलवायु नियमन जैसी चीजें शामिल हैं, जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती हैं और जल शोधन, जो हमारे पानी को साफ रखने में मदद करता है। सांस्कृतिक सेवाओं में शामिल हैं वे चीजें हैं जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं जो कम मूर्त हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें बाहरी मनोरंजन, शिक्षा और आध्यात्मिक संवर्धन के अवसर जैसी चीजें शामिल हैं। वे हमारी सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में भी मदद करते हैं। सहायक सेवाएं वे चीजें हैं जो अन्य सभी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को रेखांकित करती हैं। इनमें मिट्टी का निर्माण, पोषक चक्रण और जैव विविधता संरक्षण जैसी चीजें शामिल हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति को ठीक से काम करने में मदद करती हैं और हमें वे सेवाएं प्रदान करती हैं जिन पर हम निर्भर हैं।

पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की इन विभिन्न श्रेणियों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन और हमारी भलाई के लिए प्रकृति के महत्व की सराहना करने में हमारी सहायता करती है। यह हमें अपने और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए पर्यावरण के प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। पारिस्थितिक तंत्र मानव जीवन के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, आवश्यक संसाधन, सेवाएं और लाभ प्रदान करते हैं।

भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता भारत, मोदी ने इस मिथक को तोड़ा

सुरेश हिंदुस्तानी

देश को अच्छा वातावरण देने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली की चाह हर किसी की होती है। क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरे तक समाती चली जा रही हैं। लेकिन यह भी एक बड़ा सच है कि जो भ्रष्टाचार का शिकार होता है, वह अनीति के मार्ग पर कदम बढ़ाने का दुस्साहसिक कार्य ही करता है। सैद्धांतिक तथ्य यह है कि जितना भ्रष्टाचार करने वाला दोषी है, उतना ही भ्रष्टाचार का शिकार होने वाला भी दोषी है, इसलिए दोनों का ही जीवन कुसंस्कार की बलि चढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो परिश्रम करके खाता है, उसके जीवन में संतोष होता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करके खाता है, उसको कई लोगों के हृदय से उफनती हुई गालियों को झेलना होता है यानी उसको बद्दुआ ही मिलती है।

कांग्रेस के शासन काल के दौरान जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के काले कारनामे उजागर होते जा रहे थे, उससे तो ऐसा ही लगता था कि अब देश से भ्रष्टाचार रूपी बुराई का अंत नहीं हो सकता, यह सामान्य अवधारणा के रूप में स्थापित हो चुका था कि यह देश का स्वभाव बन चुका है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से देश में नरेन्द्र मोदी की सरकार आई है, तब से केन्द्र सरकार पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इसका कारण स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार की इस मामले में स्पष्ट नीति है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ही यह कहकर भ्रष्टाचार मिटाने की संकल्प लिया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। कहा जाता है कि जब शासनकर्ताओं की नीयत साफ होती है तो नीचे भी संदेश अच्छा ही जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक कार्यक्रम में एक बार फिर से इस

आशय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। यानी केन्द्र सरकार आज भी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संकल्पित है। वर्तमान में केन्द्र सरकार के स्तर से भ्रष्टाचार मिटाने की ठोस पहल की जा रही है। इतना ही नहीं आज केन्द्र सरकार ने देश में घर कर चुकी इस आम धारणा को बदला है कि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत केवल केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से ही संभव हो सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए देश की राज्य सरकारों को भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग करना चाहिए। इसके लिए सरकार को जांच एजेंसियों का सहयोग लेना चाहिए।

यह बात सही है कि देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक ऐसी संस्था है, जिस पर हर कोई विश्वास करता है। देश में किसी भी घटना में न्याय की उम्मीद नहीं दिखने पर लोग सीबीआई जांच की मांग भी इसलिए ही करते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच के मामले में एक विश्वसनीय संस्था है। पिछले कुछ सालों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ऐसे लोगों पर हाथ डालने का साहस दिखाया है, जिस पर हाथ डालने की किसी ने हिम्मत नहीं की। ऐसे लोगों द्वारा देश के धन पर एक प्रकार से डाका ही डाला था। सरकारी खजाने की लूट करने वाले इन भ्रष्टाचारियों पर अगर सीबीआई ने कार्रवाई की है, तो इसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला ठोस कदम ही माना जाना चाहिए, लेकिन देश में विपक्षी दलों की ओर से जिस प्रकार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच को आधार बनाकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा गया, वह उनकी मानसिकता को उजागर करने के लिए काफी है। सवाल यह आता है कि अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार के रूप में कमाई नहीं की है तो इनको डर क्यों लग रहा है? डरता वही है, जो गलत होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर दोष सिद्ध होने के बाद भी उनकी ओर से सीबीआई पर आरोप लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं, इसलिए वे भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी प्रकार बातें करते हैं तो वे सार्थक नहीं कही जा सकती। ऐसा नहीं है कि ऐसी भाषा केवल लालू प्रसाद यादव ही बोलते हैं, इसके इतर भी विपक्ष के अन्य राजनेता भी उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली उक्ति को चरितार्थ करते दिखाई देते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो यह कहा जाना समीचीन होगा कि भ्रष्टाचार के कारण अपेक्षित विकास की राह में अवरोधक पैदा होते हैं। सरकार की योजनाएं धरातल पर उस तरीके से नहीं पहुंच पातीं, जैसा सरकार चाहती है। पहले योजनाओं के लिए जो पैसा आता था, वह अधिकतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जिस हितग्राही को एक हजार रुपए मिलना है, उसे पूरा एक हजार मिलता है। भ्रष्टाचार करने वालों का यही एक ऐसा दर्द है, जिसे केन्द्र सरकार ने करेले जैसे स्वभाव पर नीम चढ़ा दिया है। केन्द्र सरकार के इस अभियान को जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, उस प्रकार से विपक्ष द्वारा भी समर्थन मिल जाए तो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले आठ वर्षों के दौरान जिस प्रकार से छापे मारी की है, उसमें कई बड़े लोगों के पास करोड़ों की अवैध संपत्ति मिली है। खास बात यह है कि यह ऐसे लोग हैं, जिनको स्वयं भी इस बात का अहसास नहीं था कि सीबीआई इन पर भी छापामार कार्रवाई कर सकती है। इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण ही एक मात्र कारण था। अब इस प्रकार के संरक्षण में बहुत भारी कमी आई है। इसी के चलते सीबीआई बिना किसी संरक्षण के उन मठाधीशों पर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाती है, जिनके यहां काली कमाई के रूप में संपत्ति के संकेत मिलते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐसा करना आवश्यक भी है। इसलिए राज्यों को भी केन्द्र का सहयोग करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कार्य आम जनता को राहत प्रदान करने वाले ही होंगे।

गांधी आज

सत्याग्रह के प्रकार

सत्याग्रह जितनी रीतियों से हो सकता है उन सबको गिनाया नहीं जा सकता। अधर्म का स्वरूप, उसकी तीव्रता, उसका आचरण करनेवाले व्यक्ति या समाज की विशेषताएँ, उसका और अपना संबंध, हमारा तथा जिसका पक्ष हमने लिया है उसके जीवन में उस अधर्म को मिटा डालने में मिली हुई सिद्धि-सत्याग्रह की पद्धति, प्रकार और मात्रा इन सब बातों पर आश्रित होती है।

साधारणत: यह कहा जा सकता है कि एक कुटुंब में रहनेवाला व्यक्ति अधर्म करनेवाले दूसरे व्यक्तियों के साथ जिन-जिन पद्धतियों का अवलंबन कर सकता है सब पद्धतियाँ उचित रूप में समाज में भी बरती जा सकती हैं।

इस प्रकार इसमें समझाने-बुझाने से शुरू करके उपवास, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उस कुटुंब, समाज, राज्य इत्यादि का त्याग, अपने न्याय अधिकार का शांति के साथ उपयोग और यह सब करते हुए जो संकट आ जायं उनको सह लेना, इत्यादि अनेक प्रकार होते हैं।

इनमें से उचित उपाय और उसकी उचित मात्रा के चुनाव में विवेक अथवा तारतम्य बुद्धि से काम लेना चाहिए। यह अनुभव से आने वाली बात है, पर कुछ उपयोगी सूचनाएं अगले प्रकरणों में दी गई हैं।

परंतु याद रहे कि सत्याग्रह ऐसी शक्ति है जिसका पूर्ण विकास अभी नहीं हो पाया है। जो तपस्वी मनसा वाचा कर्मणा, सत्य और अहिंसा का पालन करता हुआ इसकी शक्तियों की शोध में श्रम करेगा उसे इसके अनेक नए प्रकार मिलेंगे और उसे इसका बल अटूट जान पड़ेगा।

सत्याग्रह में युद्ध को रोकने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इस शक्ति का बाह्य रूप कैसा होगा यह आज नहीं कहा जा सकता। पर इसका अर्थ इतना ही है कि अधिक श्रद्धा रखकर इसकी शक्तियों के शोधन में श्रम करना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

रेल प्रशासन के खिलाफ लोको स्टाफ ने की नारेबाजी, न्यायिक जांच की मांग

बिलासपुर। बिलासपुर में शुक्रवार को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंहपुर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद लोको रनिंग स्टाफ का आक्रोश बढ़ गया। लोको स्टाफ की मौत को लेकर रनिंग स्टाफ लड़ाई के लिए तैयार है। साथ ही रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। इस मामले के सामने आने के बाद लोको स्टाफ का आरोप है कि रेल प्रशासन उनसे तय नियमों के विपरीत काम ले रहा है। रनिंग स्टाफ 9 घंटे की जगह 14-14 घंटे काम कर रहा है। जिससे रनिंग स्टाफ को आराम नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हादसे हो रहे हैं। यही नहीं रनिंग स्टाफ को ड्यूटी चेंज, रेस्ट रूम, लॉन्ग हॉल प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने इस हादसे को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही सिस्टम को फैलियर बताते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 584 नए केस आए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। लगातार प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जिसमे पिछले 24 घंटे में 584 केस आए। वही रायपुर में 101 नए मामले सामने आए हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों के अनुसार दुर्ग 38, राजनांदगांव 46, बालोद 24 बेतरामे 24, कबीरधाम 9, रायपुर 101, धमतरी 14, बलौदाबाजार 8, महासमुंद 23, गरियाबंद 5, बिलासपुर 20, रायगढ़ 27, कोरबा 16, जांजगीर-चांपा 15, मुंगेली 2, जीपीएम 28, सरगुजा 60, कोरिया 31, सूरजपुर 31, बलरामपुर 3, जशपुर 2, बस्तर 7, दांतेवाड़ा 5, सुकमा 4, कांकेर 30, नारायणपुर 1, बीजापुर 10 मरीज मिले हैं।

धान संग्रहण केंद्र के गोदाम में लगी आग, तीन करोड़ का हुआ नुकसान

सक्ती। सक्ती जिले के धान संग्रहण केंद्र के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में रखे लगभग चार लाख बोरे जलकर खाक हो गए, जिनकी कीमत तकरीबन तीन करोड़ रुपए बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की तीन गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार, धान संग्रहण केंद्र में चार लाख लगभग बोरे रखे हुए थे, गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से लगभग तीन करोड रुपए के खाली बोरे जलकर खाक हो गए। वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे दमकल की तीन गाड़ी भी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी है यह कारण अज्ञात है, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी।

सड़क निर्माण के लिए खोदे गड्ढे में बाइक सहित गिरा अधेड़

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बीती रात एक अधेड़ सड़क के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक के साथ गिर गया। हादसे में अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अधेड़ डेयरी संचालक था और काम निपटाने के बाद घर वापस लौट रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में पीडब्ल्यूडी के अफसरों के प्रति आक्रोश देखा गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को सिम्स भिजवाया। यह घटना बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के मंगला-लोखंडी के बीच जर्जर सड़क को बनाया जा रहा है। इसके लिए सड़क पर ही गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया। बुधवार की रात करीब 10 बजे डेयरी संचालक कृपाल सिंह (63) बाइक से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान रात के अंधेरे में वह बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। हादसे में कृपाल सिंह की मौत हो गई। आसपास के लोगों डायल 112 को सूचना दी। पुलिस पहुंची और उन्हें बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में अधेड़ गिर गया था उसमें पहले भी कई लोग गिरकर घायल हुए हैं। फ्लिहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्याम नारायण सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश से किया मुलाकात

कोरबा। राजीव युवा मितान के जिला संयोजक श्याम नारायण सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव मे राजीव युवा मितान की भूमिका को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव युवा मितान समाज के लिए एक सहयोगात्मक योजना हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मितान के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश मे इस योजना का लाभ जनता ले रही है और आने वाले समय पर इसमें और भी विस्तार एवं बदलाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव मे मितान क्लब की भागीदारी को लेकर आश्वासन दिया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सोनी, नरेंद्र तिवारी, जितेन्द्र साहू, मो.आबिद, संजय पटेल भी उपस्थित थे।

शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो जीवन में परिवर्तन लाता है-मुख्यमंत्री

प्रदेश में अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 708 युवाओं को दी गई नौकरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति 'पहाड़ी कोरवा' और 'बिरहोर' जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र का वर्चुअल रूप से वितरण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट-मुलाकात के दौरान विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दिलाने की घोषणा की थी। जिस पर अमल करते हुए आज 142 युवाओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया।

गौरतलब है कि इससे पहले भी जशपुर जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में पहाड़ी कोरवा जनजाति के अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार 57 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। प्रदेश में अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 708 युवाओं को शासकीय नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री निवास में इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और आदिम जाति विकास विभाग की संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी भी उपस्थित थीं। संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज और विधायक श्री विनय भगत कार्यक्रम स्थल से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो जीवन में परिवर्तन लाता है। शिक्षा ही आगे बढ़ने मार्ग प्रशस्त करती है। श्री बघेल ने कहा कि आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई की। आपके माता-पिता का आशीर्वाद भी आप के साथ रहा। आप शिक्षक बने हैं, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। इनका अधिक से अधिक अपने समाज में प्रचार-प्रसार करे ताकि विशेष पिछड़ी जनजातियों के अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जनजातीय समाज परंपरागत रूप से विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज में कुछ समुदाय बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। इन समुदायों को हम विशेष पिछड़ी जनजातीय के रूप में जानते हैं। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य शासन द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इन समुदायों के पढ़े-लिखे नौजवानों को शासकीय सेवाओं में उनकी पात्रता के अनुसार सीधी नियुक्ति दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमने पेसा कानून के सबसे बेहतर नियम लागू किए हैं। 65 प्रकार की वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और उनके प्रसंस्करण से वनवासियों को रोजगार और आय के अच्छे साधन मिल रहे हैं। कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य तय करके उनकी खरीदी की व्यवस्था की गई है। इन फसलों के लिए भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा की इन युवाओं ने बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की है। सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलने से इन समुदाय में पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ेगा।

आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि एक शिक्षक के रूप में आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज और विधायक श्री विनय भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोडने के लिए राज्य शासन द्वारा इन जनजातियों के 142 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

आदिम जाति कल्याण विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि जशपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वाधिक 199 युवाओं को शासकीय नौकरी दी गई है। इसी तरह बलरामपुर जिले में 95 तथा कबीरधाम जिले में इन जनजातियों के 80 युवाओं को नौकरी दी गई है। कलेक्टर जशपुर डॉ. रवि मित्तल ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के जिन युवाओं को आज नौकरी दी गई, उनमें हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उतीर्ण 124, स्नातक उत्तीर्ण 11 एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 06 पहाड़ी कोरवा शामिल है। बिरहोर समुदाय के भी 01 अभ्यर्थी को भी नियुक्ति दी गई है। जो हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तत्परता से करें कार्यवाही- मंत्री डहरिया

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज प्रदेश के नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक का यह दूसरा दिन है। नगरीय निकाय के इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को बारिश के पहले प्रारंभ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का अधिक से अधिक लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। इसके अलावा शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिलाने आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बीजापुर जिले के नगर पंचायत भोपालपट्टनम में नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में यहां से महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के लिए बसों का आवागमन होता है। नगर पंचायत गीदम में पालिका बाजार के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सीएमओ को दिए। मंत्री डॉ. डहरिया ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण नगर पंचायत केशकाल, खोगापानी, पुसौर, बिलाईगढ़ एवं कोतबा के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मंत्री डॉ. डहरिया ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालन की जानकारी लेते हुए इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आधे से कम दाम पर उच्च गुणवत्तायुक्त दवा नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। केबिनेट मंत्री ने नगर पंचायतों में पौनी पसारी योजना के अंतर्गत दुकानों का निर्माण एवं उसके आबंटन की जानकारी ली। डॉ. डहरिया ने सभी निकायवार मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए इसका प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। केबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्लेसमेंट कर्मचारियों का मानदेय भुगतान की कार्यवाही पहले की जावे तत्पश्चात नियमित कर्मचारियों का वेतन भुगतान करें। डॉ. डहरिया ने राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बेरोजगारी भत्ता योजना: 5535 युवाओं ने किया आवेदन

आवेदन में पूरे राज्य में बिलासपुर चौथे स्थान पर

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना के तहत जिले में अब तक 5 हजार 535 युवाओं ने आवेदन किया है। पूरे राज्य के 33 जिलों में आवेदन के मामले में बिलासपुर चौथे स्थान पर है। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले में दस्तावेजों का सत्यापन क्लस्टर में किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में वार्डों के समूह का क्लस्टर बनाकर दस्तावेज सत्यापित किये जा रहे है, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज के सत्यापन के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाके को मिलाकर कुल 107 सत्यापन केंद्र बनाए गए है। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 459 कर्मचारी तैनात किये गये है। कलेक्टर के निर्देश पर भीषण गर्मी के हालात को देखते हुए सत्यापन केंद्रों में

आवेदकों के लिए बैठने, पानी, हवा और छाया की समुचित व्यवस्था की गई है। आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जा रहा है। सत्यापन के लिए जनपद पंचायत बिल्हा में 13 क्लस्टर, मस्तूरी में 25, कोटा में 20 और तखतपुर में 15, नगर निगम बिलासपुर में 16, बिल्हा नगर पंचायत में 3, मल्हार में 3, बोदरी में 3, कोटा में 3, रतनपुर में 3 और तखतपुर में 3 क्लस्टर इस प्रकार जिले में कुल 107 क्लस्टरों में सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सत्यापन के लिए आए युवाओं का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन कार्य के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है। हमें एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है, इसके अलावा दूरभाष पर भी पृथक से सूचित किया जा रहा है। किसी कारणवश यदि हम सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो हमें अन्य दिन का शेडयूल दिया जाता है। युवाओं ने कहा कि यह योजना सपने पूरे करने में मददगार साबित होगी। राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके कैरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी हद तक मददगार होगी। बिल्हा विकासखंड के ग्राम डंगनिया के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में सत्यापन करवाने ग्राम भरवीडीह से आई सुश्री गीतांजली कमल ने बताया कि यहां सत्यापन का कार्य व्यवस्थित रूप से पूरा हो गया। उन्होंने यहां की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की।

28 को सरगुजा व 29 अप्रैल को बिलासपुर संभाग की बैठक

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 28 अप्रैल 2023 को दोपहर 12 बजे, राजीव भवन अंबिकापुर में सरगुजा संभाग तथा 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होटल-इंटरसिटी, जगमल चौक, दयालबंद, बिलासपुर में बिलासपुर संभाग के समस्त जिला, शहर, नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी पदाधिकारी की बैठक लेकर बूथ-सेक्टर-जोन कमेटियों के गठन की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. चंदन यादव एवं प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी अरूण सिसोदिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 27 अप्रैल गुरूवार को दोपहर 12 बजे रायपुर से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे राजीव भवन, अंबिकापुर में सरगुजा संभागीय बूथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। शाम 5 बजे अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। 29 अप्रैल 2023 शनिवार को दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन, बिलासपुर में बिलासपुर संभागीय बूथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। शाम 5 बजे बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे।

भुनेश्वर साहू के परिजनों ने बयान कराया दर्ज

बेमेतरा। बेमेतरा के बिरनपुर में हिंसक झड़प में मारे गए भुनेश्वर साहू के परिजनों का बयान के लिए आज दुर्ग संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे। जहां संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने घटना के संबंध में मृतक परिजनों का बयान लिया गया है। मृतक के परिजनों ने इस दौरान अपना बयान तो दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने हत्या करने वाले सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की है। मृतक भुनेश्वर साहू की अस्थियों का विसर्जन करने के बाद आज उसके परिजनों का बयान दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे द्वारा लिया गया। जिसमें परिजनों ने बिरनपुर में हुई अपने बेटे की बर्बरतापूर्ण हत्या की सारी दास्तां दुर्ग संभाग को बताई है। करीब 40 मिनट तक के बयान को परिजनों ने विस्तारपूर्वक बताया है। बयान देने के बाद हिसंक झड़प में मारे गए भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई मुआवाजा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। उनके बेटे की हत्या करने वाले हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सरकार पर विश्वास भी है।

एक्सिस बैंक में 16 करोड़ का घोटाला अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार

- पुलिस ने एक अंतरराज्यीय आरोपी को बेंगलुरु से दबोचा

रायपुर। एक्सिस बैंक में ठगी मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 16 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी के मुजगहन थाना क्षेत्र डुंडा के एक्सिस बैंक में आरोपियों ने फर्जीवाड़ करके करोड़ों रुपए का गबन किया था। रायपुर एक्सिस बैंक कलस्टर हेड प्रार्थी बी आनंद ने थाना मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के बैंक खाता क्रमांक 900010025774139 हैं। इसमें आरोपी सतीश वर्मा और चंद्रभान सिंह ने सहयोगी के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है।

आरोपियों ने फर्जी चेक बुक से बैंक से फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफर कराया। फर्जी चेक बुक से अन्य बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराया गया। आरोपियों ने खुद के लाभ के लिए बैंक को नुकसान पहुंचाया और कूटरचना कर बैंक से करीबन 16 करोड़ 40 लाख 12 हजार 6 सौ 55 रुपय का धोखाधड़ी की। प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 105/22 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 409, 419 के तहत अपराध दर्ज कराया है।

अलग-अलग राज्यों से 9 आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों की पतासाजी की गई। पुलिस टीम ने 5 आरोपियों को रायपुर और दुर्ग से, 2 आरोपियों को हैदराबाद से, 1 आरोपी को बेंगलुरू और 1 आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर कर्नाटक के बेंगलुरूनिवासी इसरार सलीम के जम्मू और कश्मीर के खाते में 1 करोड़ 98 लाख 38 हजार 998 रुपए मिले हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपने परिजनों को देना और खर्चा करना बताया। आरोपी बैंगलोर थाना बनासबाड़ी निवासी इसरार सलीम को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। प्रकरण में अब तक नगदी रकम 2 करोड़ 34 लाख रुपए, अलग-अलग बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 18 लाख रूपये को होल्ड कराया गया है। इस प्रकार कुल 3 करोड़ 52 लाख रुपए जब्त किया गया है।

भाजपा के पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की

अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा नहीं जोड़ पाई थी अपने पार्षद

बालोद। बालोद जिले की गुरुर नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी ने गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उपाध्यक्ष प्रमोद सोनवानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की है। यह विषय हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि इससे ठीक 1 वर्ष पूर्व नगर पंचायत के पार्षदों ने मंडल अध्यक्ष कौशल साहू के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मंडल अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी स्वयं पीछे हट गए थे और पार्षद भी दो गुटों में हो गए थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी। बावजूद इसके जिला एवं प्रदेश संगठन ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया अब क्योंकि उपाध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसमें मंडल अध्यक्ष कौशल साहू ने सीधे-सीधे खुद को मामले से दरकिनार करते हुए कहा कि पार्षदों से बात कर लो मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। जबकि वो तस्वीरों में स्पष्ट देखे जा रहे हैं।

तीन सीट हार चुकी भाजपा के लिए ऐसे मंडल अध्यक्ष कहीं ना कहीं पार्टी को हासिए पर ले जा रहे हैं आज भी अध्यक्ष को लेकर कोई स्पष्ट नीति भाजपा नहीं

अपना पाई है। वहीं आज के अविश्वास प्रस्ताव के पत्र में एक बात यह देखने के मिली है कि इस पत्र में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने सील पैड में अध्यक्ष नाम के अंकित किया है। इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव का पत्र काफी पुराना है जिसे आज दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव ने इस तस्वीरों में ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे।

पहले अध्यक्ष के अविश्वास में टूट गई भाजपा

पूरे विषय में जब विधायक संगीता सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा की भाजपा झुंझलाहट में ऐसा काम कर रही है यह जो पत्र है शायद पहले से बना हुआ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र है। अब भाजपा की बात करें तो अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में 4 पार्षद अलग और 3 पार्षद अलग थे अब भला ऐसे में जो अपने पार्षदों को नहीं जोड़ पाई वो अब उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत के कामों को रोककर नगर का विकास रोककर भाजपा अपनी राजनैतिक रोटी सेकना चाहती है। जनता जानती है कि भाजपा केवल विकास को प्रभावित करने इस तरह के हथकंडे अपना रही है।

विकास कार्यों में बाधा का आरोप

भारतीय जनता पार्टी के जिन पार्षदों ने आज अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की है उसमें एक निर्दलीय पार्षद टिकेश्वरी साहू का भी दस्तखत है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रमोद सोनवानी द्वारा विकास कार्यों में हमेशा से बाधा उत्पन्न की जाती है इसके कारण नगर पंचायत क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है। इसके कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पार्षदों ने यह पत्र कलेक्टर के नाम सौंपा है।

मण्डल अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर संदेह

मंडल अध्यक्ष कौशल साहू की कार्यप्रणाली पर स्वयं भाजपाई ही संदेह लगाते नजर आ रहे हैं। यहां पर भाजपा के प्रसाद ही उनके खिलाफ भाजपा जिला संगठन प्रभारी मधुसूदन यादव के समक्ष शिकायत कर चुके हैं। जिसको लेकर अब तक संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी है वहीं ग्रुप से मण्डल अध्यक्ष द्वारा कई क्रायकर्ताओ को हटाया गया था जिसको लेकर भी कौशल साहू की शिकायत हुई थी। बावजूद इसके मंडल अध्यक्ष के खिलाफ अब तक न कोई कमिटी बैठी ना ही कोई कार्रवाई की गई है। संजारी बालोद में सुस्त पड़े इस भाजपा को तारने कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है जो भाजपा अध्यक्ष पद के लिए अपने पार्षदों को नहीं जोड़ पाई वो उपाध्यक्ष के लिए कितनी सक्रियता दिखा पाती है।

सूरज ढला तो,कद से ऊँचे हो गए साये...

पीएम की डिग्री नहीं दिखाएंगे,पीएम केयर्स फंड का ब्यौरा नहीं देंगे,पीएम और अडानी के रिश्ते के बारे में मौन रहेंगे,अडानी को कोयला खान देने कैसे नियम बदल गये?नोटबंदी के क्या फायदे हुए इस पर कुछ नहीं कहेंगे,पनामा पेपर्स की जाँच नहीं करेंगे, दूसरे दलों से भाजपा में हकाल कर लाए गये दागी नेताओं की ईडी,सीबीआई जाँच थमी रहेगी.... ये मामले तो चर्चा में रहे हैं वहीं हाल में मोदी सरकार द्वारा बनाए गये पूर्व राज्यपाल के पुलवामा हमले पर लगाये गये आरोप,संघ के पदाधिकारी पर रिश्वत की पेशकश पर कोई जवाब आएगा ऐसा लगता तो नहीं हैं?कायदे से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक का आरोप यदि गलत है तो भाजपा कानूनी कार्यवाही की पहल क्यों नही की

है।जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज़ दावे किये हैं।उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफ़िले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था।उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ख़ासतौर पर से ज़िम्मेदार बताया है।उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे।मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने, सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी,लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।उन्होंने सीआरपीएफ का काफ़िला जाते वक़्त रास्ते की उचित तरीक़े से सुरक्षा जांच न कराने का भी आरोप सरकार पर लगाया है।उन्होंने पीएम मोदी पर जम्मू और कश्मीर के बारे में %अनजान% रहने की बात करते हुए कहा है कि उनके पास राज्य के बारे में ग़लत सूचनाएं हैं, राज्य को ख़ास दर्जा देने को उन्होंने एक ग़लती क़रार दिया है।सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिम कार्बेट पार्क से जब उन्हें कॉल किया और इस मसले को उनके समक्ष उठाया तो उनके अनुसार, इस पर पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने और किसी से कुछ न बोलने को कहा.... !मलिक ने बताया कि यही बात एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे कही।इस इंटरव्यू में मलिक ने बताया कि तभी उन्हें अनुभव हो गया कि सरकार का इरादा इस हमले का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना है।मलिक ने इस हमले के लिए ख़ुफ़िया एजेंसियों की विफलता को भी ज़िम्मेदार क़रार दिया है. उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान से 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर आया कोई ट्रक 10 से 15 दिनों तक जम्मू और कश्मीर में घूमता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक न लगी?सत्यपाल मलिक ने भाजपा,संघ के नेता राम माधव पर लगाया पुराना आरोप फिर दोहराया है।उन्होंने कहा कि राम माधव एक दिन सुबह सात बजे आए और कहा कि एक पनबिजली परियोजना और रिलायंस की एक बीमा योजना को मंज़ूरी देने के बदले उन्हें 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने वो पेशकश ख़ारिज करते हुए कहा कि वे ग़लत काम नहीं करेंगे।मलिक ने भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पीएम को करप्शन से बहुत नफ़रत नहीं है।

अतीक बंधु की हत्या, अनसुलझे सवाल

माफिया से राजनेता का सफर तय करने वाले उप्र के अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की

प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपियों ने पूरी वारदात ऑन कैमरा किया। अतीक और अशरफ की हत्या के वीडियो को पूरे देश ने देखा। हत्यारों ने वारदात के बाद फरार होने का दुस्साहस नहीं किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। हत्यारों की उम्र 20 से 25 साल के बीच हो सकती है। अभी तक उनका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है।एक दिन पहले तक अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर को लेकर उप्र पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही थी,अब इस डबल मर्डर के बाद सवाल भी खड़े हों रहे हैं । समूचे विपक्ष ने योगी सरकार और यूपी की कानून व्यवस्था को घेरा है।कुछ अहम सवालअब उठ रहे हैं,पुलिस के घेरे में तीन शूटर कैसे घुसे।

अतीक और अशरफ हाईप्रोफाइल कैदी थे,फिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई।अतीक और अशरफ की सुरक्षा हल्के में क्यों ली गई.. !हमलावरों को महंगे हथियार किसने मुहैया कराए।अतीक और अशरफ की हत्या की सुपारी किसने दी।बहरहाल जैसा हत्याकांड को बताया रहा है वैसा तो निश्चित नहीं लगता है?

बाबा की बयानबाजी और विपक्ष का मजा..

सरगुजा के महाराज, छग सरकार के मंत्री टी एस सिंहदेव की सीएम बनने की इच्छा बीच- बीच में हिलोरें मारने लगती है, पत्रकार पूछते हैं तो कभी वे कहते हैं कि वे सीएम बनना क्यों नहीं चाहेंगे।कभी कहते हैं कि हाई कमान का पहले जैसा हाँथ अब उनके कंधे पर नहीं नजर आता है।वे 2014 में छग की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। खैर छग बनने के बाद श्यामाचरण शुक्ला, विद्या चरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा आदिवासी नेता महेन्द्र कर्मा के दावे के बाद भी एक नौकरशाह,गैर विधायक अजीत जोगी को पहला सीएम बनाया गया। जहाँ तक भाजपा की बात है तो रमेश बैस, दिलीप सिंह जूदेव, नंद कुमार साय,लक्खी राम अग्रवाल को हासिये में रखकर डॉ रमन सिँह को 3 बार सीएम बनाया गया, हालांकि रामविचार नेताम, ननकी राम कंवर आदि बीच बीच में आदिवासी एक्सप्रेस भी चलाते रहे पर कुछ हुआ नहीं।जहाँ तक छग में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 दाऊजी (बड़े दाऊ डॉ चरण दास महंत,छोटे दाऊ भूपेश बघेल) टी एस सिंहदेव तथा ताम्रध्वज साहू का नाम चला था पर भूपेश के पक्ष में कॉंग्रेस हाईकमान ने निर्णय दिया। बीच में ढाई -ढाई साल के फार्मूले की भी चर्चा चली।

अब अगले विस चुनाव को कुछ माह ही बचे हैं और सीएम भूपेश बघेल का कद इतना बढ़ गया है कि अब बदलाव की दूर -दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, जब दूसरे राज्यों में भूपेश को चुनाव कराने भेजा जाता है तो अपने छग में तो अगला चुनाव भूपेश के नेतृत्व में ही

होगा यह तय है ऐसे में बाबा के बयान के कोई मायने नहीं हैं, हाँ उनके बयान का विपक्ष जरूर मजा लेने में पीछे नहीं हैं...जबकि बाबा पहले ही कह चुके हैं कि वे किसी भी हालत में भाजपा नहीं जाएंगे?

जुनेजा ही विस,लोस चुनाव करवाएंगे

अशोक जुनेजा छग में पूर्णकालीन डीजीपी 5 अगस्त 22 को बन गये थे, गृह विभाग ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस बल के प्रमुख पदभार ग्रहण करने के बाद 2 साल तक इस पद पर बने रह सकेंगे। इस हिसाब से जून में जुनेजा रिटायर नहीं होंगे क्योंकि छग सरकार फिलहाल उन्हें हटाने के मूड में नहीं है।वे अगस्त24 में रिटायर होंगे यानि अगला विस तथा लोस चुनाव वहीं करवाएंगे।यूपीएससी की अनुशंसा के बाद अब जुनेजा अगस्त 24 में रिटायर होंगे,पहले वे जून 23 में रिटायर होने वाले थे।इधर विशेष डीजी राजेश मिश्रा जनवरी 24 में रिटायर होंगे इसलिये ये तो दौड़ से बाहर ही हो गये हैं?वहीँ अरुण देव गौतम जुलाई 27, पवन देव जुलाई 28, हिमांशु गुप्ता जून 29, जीपी सिंह जून 29 (अभी निलंबित), एसआर पी कल्लूरी मई 31,प्रदीप गुप्ता जुलाई 31, विवेकानंद सिन्हा जनवरी 32, दीपांशु काबरा जुलाई 34 में रिटायर होंगे। इधर प्रतिनियुक्ति पर होनेवाले वरिष्ठ आईपीएस रवि सिन्हा जनवरी 24,स्वागत दास नवम्बर 24, जयदीप जुलाई 30 में रिटायर होंगे तो एडीजी तथा सीबीआई में संयुक्त संचालक पदस्थ अमित कुमार दिसंबर 35 में सेवानिवृत होंगे।

और अब बस.....

- संयुक्त राष्ट्र (यूएनएफपीए) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है।भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं।
- ईडी तथा सीबीआई छग में कोयला स्केम, शराब, डी मएफ और महादेव ऐप (ऑन लाइन सट्टा)चार मामलों में जाँच कर रही है।
- पहली बार राजधानी के कलेक्टर,एसपी को एक साथ हटाने की चर्चा है?
- एक वरिष्ठ आईएएस को डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना वाली जगह में क्यों पदस्थ किया गया है?
- छग का कौन सचिव अगला विस चुनाव लड़ने की तैयारी में है?
- कोरबा जिले में पदस्थ एसडीएम पर उनकी पत्नी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस संगठन के बीच बदलाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता का तंज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं और प्रदेश सरकार में कोहराम की गूंज सुनाई पड़ रही है। श्री गुप्ता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चल रही सियासी कवायद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह उठापटक इस बात की तस्दीक करती है कि कांग्रेस के अंदरखाने सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव है। चुनावी वर्ष में कांग्रेस में इस ऊहापोह की परिणिति किस रूप में होगी? भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। कई दिनों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की ख़बरें सियासी पारे को गर्म कर रही हैं। लेकिन, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की घोषणा हाईकमान नहीं कर पा रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाईकमान के अनिर्णय की स्थिति की वजह यह है कि जो बदले जाने हैं, उनका एक गुट है जो संगठन पर दबाव डाल रहा है, इधर नए संभावित प्रदेश अध्यक्ष का भी अपना एक गुट है। इसलिए बार-बार यह खबरें आती है कि वो आने वाले हैं औरये जाने वाले हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसी दशा में जाने वाले और आने वाले के बीच में जो यह लड़ाई चल रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह बिख़र चुकी है, अंदर से टूट चुकी है।

कांग्रेस में अब वक्ताओं का भी अकाल- रंजना साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस द्वारा हर जिले में 10 वक्ता नियुक्त करने साक्षात्कार आयोजित करने पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब तक कांग्रेस

में नेताओं का अकाल सामने आ रहा था, अब लगता है कि वक्ताओं की भी कमी हो गई है जो लालटेन लेकर वक्ता खोज रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को जवाब नहीं दे पा रहे। उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। उनके विधायक जनता का सामना नहीं कर पा रहे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी भाजपा के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे इसलिए अब वक्ता खोजो अभियान चल रहा है। यह भी विचित्र बात है कि जो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, वह भी कांग्रेस का वक्ता हो सकता है। कांग्रेसी वक्ता बनने योग्य नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कहा कि कांग्रेस हर जिले में 10 क्या 100 वक्ता बना ले, लेकिन क्या सच बोलने और स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? कांग्रेस के छोटे से कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में 7 हजार बलात्कार हो गए। 3 हजार लोगों की निर्मम हत्या हो गई। 26 हजार लोगों ने इस सरकार से निराश होकर आत्महत्या कर ली। 25 हजार नवजात शिशु की मौत इलाज के अभाव में हो गई। केंद्र सरकार की कोई योजना यहां सलीके से अमल में नहीं है। केंद्र की योजनाओं की रकम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अडानी के घोटाले बाज समधी को भी मोदी सरकार ने देश से भगा दिया - कांग्रेस

रायपुर। अडानी के घोटाले को संरक्षण देने वाली मोदी सरकार ने अडानी के समधी को भी

घोटाला कर देश से भागने दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अडानी का समधी जतिन मेहता 7000 करोड़ डकार कर देश से भाग गया तथा दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। जतिन मेहता के तार मान्टेरोसा नाम की कंपनियों से जुड़े है। मान्टेरोसा समूह मारीशस स्थित शेल कंपनियों का मालिक है यह वही शेल कंपनियां है जिन्होंने अडानी समूह में पैसा लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जतिन मेहता की तीन कंपनियों - 'विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड', 'फॉरएवर प्रेशियस ज्वैलरी एंड डायमंड्स लिमिटेड' और 'सु-राज डायमंड्स' ने पंजाब नेशनल बैंक सहित भारत के अन्य सरकारी बैंकों को 6,712 करोड़ का चूना लगाया और फिर मेहुल भाई और नीरव मोदी जैसे बाक़ी भगोड़ों के जैसे भाग खड़े हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून, 2016 को भारतीय नागरिकता छोड़ दी और कैरेबियन में अंतर्राष्ट्रीय टैक्स हेवेन, सेंट किट्स और नेविस के नागरिकों के रूप में बस गए।

कोरोना को लेकर नेता प्रतिपक्ष गलत बयानी कर भय न फैलायें - कांग्रेस

रायपुर। कोरोना को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण

चंदेल द्वारा दिये गये बयान को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश में अनावश्यक भय फैलाने वाला बताया है। कोरोना से निपटने को लेकर राज्य सरकार की पूरी तैयारी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह सजग है और कोरोना के केस मिलना शुरू होते ही राज्य सरकार ने इसके लिये गाइड लाइन जारी कर दिया है। सभी जिलों अस्पतालों, सभी मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की जांच और उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। राज्य में प्रतिदिन 6000 के लगभग लोग कोरोना की आशंका से अपना परीक्षण करवाने आ रहे है। भले ही पॉजीविटी 9 के लगभग है लेकिन संक्रमण की आशंका वाले लोगों की संख्या कम है तभी परीक्षण कराने वाले लोगों की संख्या कम है। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिये कोरोना के आंकड़ों को लेकर जो बयानबाजी कर रहे है, उससे अनावश्यक भय के हालात पैदा होते है। प्रदेश में हालात डरने वाली नहीं है, लोगों को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। जिम्मेदार पद पर बैठे हुये लोगों को कोरोना जैसे संवेदनशील मामले में सोच समझकर बयान देना चाहिये।

रमन सिंह ने पत्र में रद्द ट्रेन शुरू करने और आरक्षण सीमा हटाने की मांग क्यों नहीं की?

रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के केंद्र को लिखे पत्रों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार अपनी गिरती राजनैतिक साख बचाने केंद्र को पत्र लिखने का नया ड्रामा शुरू किये है। प्रदेश में एक दर्जन से भी अधिक मौके आये जब रमन सिंह को केंद्र को पत्र लिखना था तब नहीं लिखे, अब पत्र लिखकर खानापूर्ति कर रहे है। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब महार जाति की आरक्षण की चिंता करते तब महार समाज को 15 साल पहले आरक्षण का लाभ मिल जाता लेकिन उस दौरान रमन भाजपा की सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती करने का महापाप किये। अनुसूचित जाति में महार समाज को शामिल कराने की चिंता नहीं की। अब सत्ता जाने के बाद चुनाव नजदीक आते ही महार जाति की चिंता रमन सिंह का राजनीतिक चिंता है। रमन सिंह को पहले महार समाज से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस महार समाज को उनका हक दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ रमन सिंह को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने केंद्र सरकार को दो पत्र लिखे है उस पत्र में आम जनता की मूल समस्याओं का उल्लेख क्यों नहीं किया है? महार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के साथ आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत सीमा को हटाने की मांग क्यों नहीं किये?

केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने की नुक्कड़ सभा

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत शहर जिला कांग्रेस कमेटी अंतर्गत आने वाले सभी ब्लॉको मे नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा के दौरान बाजारो मे भारत जोड़ो यात्रा मे राहुल गांधी के आपसी भाईचारे का संदेश एवं भाजपा सरकार के गलत नीतियो के खिलाफ सांप्रदायिकता कटरता सामाजिक असमानता मंहगाई और बेरोजगारी जो देश मे पैदा हुई है। उसका पर्चा भी आमजनो को बांटा जा रहा है। नुक्कड़ सभा मे आमजनो को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि अडानी मामले की जांच ईडी क्यो नही करती, सरकारी एजेंसियो पर केंद्र सरकार का कब्जा है। जहां करोड़ो का घोटाला वहां ईडी नही जाती । एसबीआई और एलआईसी मे जनता का पैसा है केंद्र ने एसबीआई और एलआईसी का पैसा अडानी को दिया है। निगम सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि गहरे आर्थिक संकट के समय भाजपा की मोदी सरकार देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेचच रही है। शहर प्रवक्ता बंशी कन्नौजे ने जानकारी दी कि आज यह नुक्कड़ सभा शहीद भगत सिंह ब्लॉक के मोहबा बाजार चौक मेन रोड मे कन्हैयालाल बजारी ब्लॉक के खमतराई बाजार मे डॉ. खुबचंद बघेल ब्लॉक के चंगोराभाटा बाजार मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्लॉक के कर्मा चौक मे कर्मा चौक मे ले. अरविंद दीक्षित ब्लॉक के जय स्तंभ चौक मे गुरू घासीदास ब्लॉक के पंडरी झंडा चौक मे शहीद पंकज विक्रम वार्ड टिकरापारा साहू काम्प्लेक्स के पास आयोजित किया गया था।

कांग्रेस पहले खुद पर लगा कोयले का कालापन साफ करें-संतोष पांडेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी सांसद संतोष पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। वे उन भ्रष्टाचारियों की पैरवी करते हैं, जिनके यहां किलो में सोना मिला, भारी नकदी बरामद हुई, अचल संपत्ति अटैच की गई, कई महीनों बाद भी अदालत ने जिन्हें जमानत नहीं दी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के पोषक मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि इन भ्रष्टाचारियों से उनका यह कैसा नाता है कि जब इन पर कानून का शिकंजा कसा तो वे छटपटा रहे हैं। सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि भूपेश बघेल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपने राज्य में चल रहे भारी भ्रष्टाचार पर जवाब देना चाहिए लेकिन इसके बजाय वे राष्ट्रीय राजनीति में बेजा दखल देने की असफल कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार का संरक्षक हो, वह किसी अन्य पर बिना कारण आक्षेप करें तो यह समझा जा सकता है कि उन्हें अपने अंदर झांकने की सामर्थ्य नहीं है। भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के हवाले करने के लिए राज्य की जनता से माफी मांगें एक ऐसा सीएम जो स्वयं जमानत पर है, वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है।

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में सेवा इंटरनेशल स्वयंसेवी संस्था के निदेशक कुमार शुभम ने सौजन्य मुलाकात की ।

ओडीओपी उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना प्राथमिकता - संजय

रायपुर। केन्द्रीय उत्पाद एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के लिए विशेषकर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रदेशों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए मिलेट्स के उत्पाद विशेषकर बस्तर के आदिवासियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें ओडीओपी (वन डायरेक्ट वन प्रोडक्ट) के जरिए जनजागरूकता अभियान चलाकर आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की मुहिम चल रही है। इसी कड़ी के तहत आज शुक्रवार को उद्योग भवन में विभिन्न उत्पाद पैदा करने वाले उत्पादकों की समस्याओं एवं उनके निदान के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में केन्द्र सरकार की प्रतिनिधि महिला जनसंपर्क अधिकारी एवं संयुक्त संचालक संजय पठारे छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जी-20 देशों की होने वाली समिट में छत्तीसगढ़ के 10 बहुमूल्य मिलेट्स के उत्पाद भेजे गए हैं साथ ही उनका डेमो भी प्रतिनिधियों को दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी 28 जिलों में ओडीओपी के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया गया है। पत्रकारवार्ता में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्पादकों ने चर्चा के दौरान प्रमुख रूप से उत्पादों को मार्केट में लाने के लिए पैकेजिंग की समस्या का उल्लेख किया। केन्द्र सरकार की महिला जनसंपर्क अधिकारी पत्रकारवार्ता में बताय कि विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों यथा कोदो, कुटकी, रागी एवं अन्य उत्पादों को विशेषकर काला चांवल एवं अन्य बेहतरीन उत्पाद को ऑन लाइन कंपनियों अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट सहित अन्य एजेंसियों के माध्यम से ओडीओपी से जोड़कर विश्व स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादकों को अधिक से अधिक अर्धलाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय उत्पाद एवं वाणिज्य मंत्रालय के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को उत्पादों के मामले में उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ओडीओपी सर्वोत्तम प्लेटफार्म है, जिसके जरिए अब तक अनेक उत्पादकों को सर्वोच्च स्तर पर अर्धलाभ पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण में स्थानीय उत्पादकों को मेलों अथवा अन्य प्रदर्शनियों के अलावा वहीं पर अपने उत्पाद अधिकतम मूल्य पर अच्छे लाभ के साथ बेचने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। पत्रकारवार्ता में पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार तिवारी एवं छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम के लिए शासन के विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को उद्योग विभाग के जरिए समय-समय पर कार्य योजना से कार्यशाला के जरिए नवीन जानकारियों से अवगत कराया जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.